RNI No. 58061/93 ▪ वर्ष - 21 ▪ अंक - 221 ▪ पृष्ठ - 8 ▪ रु. 5/- बेंगलूरु » बुधवार » 11-03-2026 ▪ www.dakshinbharat.com ▪ Email : news@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಮತ | ಹಿಂದಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ | बेंगलूरु और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित

5 प्रियंका को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया होता तो प्रदर्शन अच्छा होता : रीजीजू

6 वैश्विक युद्धोन्माद के बीच विश्व शांति की पुकार

7 टीवी के बाद अब ओटीटी पर जादू बिखेरेंगी रूप दुर्गापाल

फर्स्ट टेक

बांग्लादेश को भारत से मिला 5,000 टन डीजल

ढाका/भाषा। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण ईंधन की किल्लत को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, बांग्लादेश को भारत से डीजल मिलना शुरू हो गया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि शुरुआती तौर पर 5,000 टन डीजल बुधवार तक मिलने की उम्मीद है। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (बीपीसी) के प्रवक्ता ने कहा, ''हमें सोमवार दोपहर से असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि. (एनआरएल) से बांग्लादेश-भारत मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से (उत्तर-पश्चिमी) दिनाजपुर स्थित डिपो में डीजल मिलना शुरू हो गया है।'' उन्होंने बताया कि 5,000 टन डीजल आने में लगभग 45 घंटे लग सकते हैं। यानी यह प्रक्रिया बुधवार शाम तक जारी रह सकती है। उन्होंने कहा, ''हम यहां प्रति घंटे पाइपलाइन के जरिये लगभग 113 टन प्राप्त कर रहे हैं।''

एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस हवाई टिकट पर ईंधन अधिभार लगाएंगी

नई दिल्ली/भाषा। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण विमान ईंधन एटीएफ की कीमतों में तेजी आने पर एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस 12 मार्च से प्रत्येक घरेलू उड़ान के टिकट पर 399 रुपये का ईंधन अधिभार लागू करेंगी। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए भी ईंधन अधिभार बढ़ाया जाएगा। मंगलवार को जारी बयान में कहा गया कि नई अधिभार प्रणाली चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। पहले चरण में, 12 मार्च से घरेलू और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) के लिए उड़ानों पर 399 रुपये प्रति टिकट का ईंधन अधिभार लागू होगा। बयान में कहा गया कि पश्चिम एशिया की उड़ानों के लिए अधिभार 10 डॉलर, अफ्रीका के लिए 90 डॉलर और दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए 60 अमेरिकी डॉलर होगा।

नेता प्रतिपक्ष 'लीडर ऑफ प्रोपगेंडा' बन गए हैं : निशिकांत दुबे

नई दिल्ली/भाषा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 'लीडर ऑफ अपोजिशन' के बजाय 'लीडर ऑफ प्रोपगेंडा' करार देते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने मंगलवार को कहा कि राहुल गांधी को देश और मीडिया गंभीरता से नहीं लेता। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लाए गए विपक्ष के संकल्प पर चर्चा में भाग लेते हुए दुबे ने कहा कि जब भाजपा विपक्ष में थी तो सदन में कई बार ऐसे मौके आए, जब टकराव की स्थिति बनी थी।

युवा आकांक्षाएं भारत की सबसे बड़ी पूंजी : मोदी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश की ''सबसे बड़ी पूंजी'' हैं और उनके नवाचार एवं योगदान की इच्छा राष्ट्र के भविष्य के लिए एक प्रमुख ताकत है।

दिव्यांगजन कौशल योजना पर बजट के बाद एक वेबिनार में मोदी ने कहा कि इस तरह के परामर्श की नई परंपरा जन भागीदारी के शक्तिशाली उदाहरण को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि वे केंद्रीय बजट के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए व्यावहारिक विचार पेश करने को लेकर विशेषज्ञों, हितधारकों और लाभार्थियों को एक साथ लाते हैं।

मोदी ने कहा, ''आज भारत की सबसे बड़ी ताकत गांवों, कस्बों और शहरों के युवाओं की आकांक्षाओं में निहित है, जो देश के भविष्य के लिए कुछ नया करना और सार्थक योगदान देना चाहते हैं।''

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे-जैसे भारत एक नवाचार-संचालित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, देश को इस क्षमता का फायदा उठाने के लिए अपनी शिक्षा प्रणाली को लगातार आधुनिक बनाना होगा।

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि केंद्रीय बजट में दिव्यांगजन कौशल योजना की घोषणा का उद्देश्य दिव्यांग लोगों के लिए रोजगार से जुड़े कौशल विकास को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि सम्मानजनक रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए सरकार, उद्योग और नागरिक समाज के बीच साझेदारी महत्वपूर्ण होगी।

वेबिनार में विशेषज्ञों ने जोर दिया कि दिव्यांगजन के लिए बाजार-आधारित कौशल ऐसे हों, जो समुदाय की आकांक्षाओं को उद्योग की मांग के साथ जोड़े और उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा, एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित) अध्ययन और रोजगार प्रणाली में समाहित करे। चर्चा में समावेशी नियुक्ति, सुलभ प्रशिक्षण उपकरण, उद्यमिता, डिजिटल प्लेटफॉर्म और एआई-सक्षम दूरस्थ कार्य अवसरों के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने दिया इस्तीफा

नई दिल्ली/भाषा। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। एक बयान में यह जानकारी दी गई है। उल्लेखनीय है कि इंडिगो पिछले तीन माह में अपने परिचालन में बड़े व्यवधान का सामना कर रही है। बयान में कहा गया है कि नए सीईओ की नियुक्ति तक एयरलाइन के प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया अंतरिम व्यवस्था के तहत इंडिगो के प्रबंधन का कामकाज देखेंगे।

इंटरग्लोब एविएशन के चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने कहा, राहुल एयरलाइन के प्रबंधन का कार्य संभालने लौट रहे हैं ताकि कंपनी की संस्कृति को मजबूत किया जा सके, संचालन की उत्कृष्टता को और बढ़ाया जा सके और ग्राहकों को बेहतर देखभाल, भरोसेमंद सेवा और पेशेवर अनुभव प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया जा सके।

इंटरग्लोब एविएशन एयरलाइन का परिचालन इंडिगो ब्रांड नाम से करती है।

विनम्रता और संयम के साथ अपने अधिकार का प्रयोग करें आयकर अधिकारी : राष्ट्रपति

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को कहा कि कर अधिकारियों को अपनी शक्तियों का प्रयोग विनम्रता, संयम और संवैधानिक मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ करना चाहिए।

राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात करने आए भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों के एक समूह को संबोधित करते हुए मुर्मू ने कहा कि कर अधिकारियों से ऐसे निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है जो न्यायसंगत, कुशल और व्यावसायिक प्रक्रियाओं की गहरी समझ पर आधारित हों।

मुर्मू ने कहा, ''मुझे विश्वास है कि आपके निर्णय और कार्य व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने तथा देश के राजस्व की रक्षा करने के बीच सही संतुलन स्थापित करेंगे।''

राष्ट्रपति ने कहा कि आईआरएस अधिकारी होने के नाते, उन्हें अपने आचरण और निर्णय लेने में सावधानी से विवेक का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्व सेवा का दायित्व कर संग्रह से कहीं अधिक व्यापक है।

राष्ट्रपति ने कहा, ''जटिल वित्तीय लेन-देन का विश्लेषण करने, सीमाओं के पार अवैध वित्तीय प्रवाह का पता लगाने और जटिल कॉरपोरेट संरचनाओं को समझने की आपकी क्षमता आपको विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में राष्ट्र की यात्रा को आगे बढ़ाने में अपरिहार्य भागीदार बनाती है।''

राष्ट्रपति मुर्मू ने आईआरएस (आयकर) के 79वें बैच के प्रशिक्षुओं अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, ''आईआरएस अधिकारी के रूप में, आप यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे कि करों की वसूली निष्पक्षता, दक्षता और पारदर्शिता के साथ की जाए।''

भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए काम करेंगे : बालेंद्र शाह

काठमांडू/भाषा। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बालेंद्र शाह ने मंगलवार को नेपाल-भारत के ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत और उन्हें अधिक परिणामोन्मुखी बनाने का विश्वास व्यक्त किया। रैपर से नेता बने 35 वर्षीय बालेंद्र शाह नेपाल के पहले मधेसी और सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ये बातें कही और पार्टी की चुनावी सफलता पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने पोस्ट में कहा, माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। शाह ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम नेपाल और भारत के बीच ऐतिहासिक, घनिष्ठ और बहुआयामी संबंधों को अधिक मजबूत, गहरा व परिणामोन्मुखी बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। नेपाल में संसदीय चुनावों में प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के तहत मतगणना मंगलवार को पूरी होने के साथ ही राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) ने 165 में से 125 सीटें जीत ली हैं, जिससे वह बहुमत की सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है। पार्टी ने आनुपातिक मतदान प्रणाली के तहत 49,74,957 वोट हासिल किए। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को आरएसपी प्रमुख रवि लामिछाने और बालेंद्र शाह को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देते हुए दोनों देशों की पारस्परिक समृद्धि, प्रगति और कल्याण के लिए उनके साथ काम करने की भारत की प्रतिबद्धता जताई। शाह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भारत सरकार और भारतीय जनता को भारतीय क्रिकेट टीम के लगातार दो बार विश्व कप खिताब जीतने पर बधाई दी।

न्यायालय ने शरिया कानून के प्रावधानों को रद्द करने की याचिका पर कहा :

यूसीसी का समय आ गया है

- हमें निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए विधायी शक्ति का सहारा लेना होगा।
- एक पुरुष की एक पत्नी' का नियम सभी समुदायों पर समान रूप से लागू नहीं हो रहा है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि अब 'समान नागरिक संहिता' (यूसीसी) लागू करने का समय आ गया है। शीर्ष अदालत ने 1937 के शरिया कानून के प्रावधानों को मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण बताते हुए निरस्त करने के अनुरोध वाली याचिका को ''एक बहुत अच्छा मामला'' बताया और कहा कि इस पर केवल विधायिका (सरकार) को ही विचार करना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि यदि न्यायालय शरिया उत्तराधिकार कानून को निरस्त करता है, तो इससे कानून में शून्य की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि मुस्लिम उत्तराधिकार को नियमित करने वाला कोई वैधानिक कानून नहीं है।

प्रधान न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण से कहा, ''सुधारों के प्रति हमारे अति-उत्साह में, हम उन्हें वंचित कर सकते हैं, और उन्हें पहले से मिल रहे अधिकारों से कम मिल सकता है। यदि 1937 का शरिया कानून खत्म हो जाता है, तो फिर सवाल क्या उठता है? क्या इससे एक अनावश्यक शून्य उत्पन्न नहीं होगा?''

न्यायमूर्ति बागची ने कहा, ''भेदभाव के मुद्दे पर आपका मामला बहुत मजबूत है, लेकिन क्या यह उचित नहीं होगा कि न्यायालय इस मामले को विधायिका के विवेक पर छोड़ दे, जिसे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (डीपीएसपी) के अनुसार, समान नागरिक संहिता लागू करने का अधिकार प्राप्त है?''

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, ''इसका उत्तर है समान नागरिक संहिता।'' न्यायमूर्ति बागची ने इस बात पर जोर दिया कि 'एक पुरुष की एक पत्नी' का नियम सभी समुदायों पर समान रूप से लागू नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, ''लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अदालत सभी बहुविवाहों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है? इसलिए, हमें निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए विधायी शक्ति का सहारा लेना होगा।'' उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को विधायिका के विवेक पर छोड़ना ही सबसे अच्छा होगा। न्यायमूर्ति बागची ने यह भी कहा, ''इस अदालत ने बार-बार विधायिका से यह सिफारिश की है कि वह समान नागरिक संहिता लागू करे।

रक्षा मंत्री ने जारी किया 'दृष्टिकोण पत्र-2047'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण पत्र जारी किया, जिसमें भारतीय सेना को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक रणनीतिक सुधार, दक्षता बढ़ाने के उपाय और संगठनात्मक परिवर्तन की एक श्रृंखला की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। यह दृष्टिकोण पत्र भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष के आठ महीने बाद जारी किया गया। पिछले साल सात से 10 मई के बीच हुए इस संघर्ष के बाद, सेना के तीनों अंगों (थलसेना, वायुसेना और नौसेना) से कहा गया कि वे इस संघर्ष से मिले अनुभव का लाभ उठाने के लिए काम करें।

इस संघर्ष के बाद, तीनों सेनाओं को इससे मिले अनुभव पर काम करने के लिए कहा गया था।

'रक्षा बल दृष्टिकोण 2047: भविष्य के लिए तैयार भारतीय सेना की रूप रेखा' में सेना को एक एकीकृत, बहु-क्षेत्रीय और सतर्क बल में बदलने की परिकल्पना की गई है, जो विरोधियों को रोकने और किसी भी संघर्ष का प्रभावी ढंग से जवाब देने में सक्षम हो।

11-03-2026 सूर्यास्त	12-03-2026 सूर्योदय
6:29 बजे	6:29 बजे

BSE	NSE
78,205.98	24,261.60
(+639.82)	(+233.55)

सोना	चांदी
16,647 रु.	273,795 रु.
(24 कैरेट) प्रति ग्राम	प्रति किलो

मिशन मंडेला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

दौर पर ग़ौर

रिश्वतखोरी हो गई आम,
मंहगाई की लग रही झड़ी।
रुजगार लापता शहरों से,
वादों की रपटें घड़ी-घड़ी।
असमंजस में बैठे किसान,
उम्मीदें उनको बड़ी-बड़ी।
नेता निंदा में लगे पड़े,
जनता की दिखती खाट खड़ी।।

ईरान ने दबाव बनाने की रणनीति के तहत इजराइल, खाड़ी देशों पर नए हमले किए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

दुबई/एपी। ईरान ने मंगलवार को दबाव बनाने की नीति के तहत इजराइल और खाड़ी देशों पर नये हमले किए। इस युद्ध ने वैश्विक बाजारों को हिलाकर रख दिया है।

संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में मिसाइलों की चेतावनी वाले सायरन बजने लगे, जबकि बहरीन में अधिकारियों ने कहा कि ईरान ने राजधानी में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया, जिसमें 29-वर्षीय एक महिला मारी गई, जबकि आठ घायल हो गए। इस बीच, सऊदी अरब ने कहा कि उसने अपने तेल-समृद्ध पूर्वी क्षेत्र में दो ड्रोन नष्ट कर दिये, जबकि कुवैत के नेशनल गार्ड ने कहा कि उसने छह ड्रोन मार गिराए हैं।

संयुक्त अरब अमीरात में, पेट्रोकेमिकल संयंत्रों वाले औद्योगिक शहर रुवैस में ईरानी ड्रोन हमले के बाद लगी आग को बुझाने के लिए दमकलकर्मी जूझते नजर आए। हालांकि, इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

यरुशलम में भी सायरन बजने लगे और तेल अवीव में विस्फोटों की आवाज सुनी गई, क्योंकि इजराइल की रक्षा प्रणालियां ईरान की ओर से हो रहे हमलों को रोकने का प्रयास कर रही थीं।

इस बीच, अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि मंगलवार को ''ईरान के अंदर हमारे हमलों का एक बार फिर सबसे भयावह दिन होगा: सबसे अधिक लड़ाकू विमान, सबसे अधिक बमवर्षक विमान, सबसे अधिक हमले, तथा खुफिया जानकारी पहले से कहीं अधिक परिष्कृत और बेहतर होगी।''

इस बयान से कुछ ही समय पहले उन्होंने कहा, ''पिछले 24 घंटों में ईरान ने अब तक की सबसे कम संख्या में मिसाइलें दागी हैं।''

वहीं, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोपहर के समय तेहरान में कई विस्फोटों की आवाज सुनाई दीं, जब इजराइल ने हवाई हमलों की एक नई झड़ी लगा दी।

इजराइल ईरानियों को मुक्ति दिलाने में मदद कर सकता है, लेकिन इसके लिए ईरानी आगे आएं : नेतन्याहू

यरूशलम/भाषा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल ईरानियों को ''तानाशाही शासन से मुक्ति'' दिलाने में मदद कर सकता है, लेकिन देश में कोई भी राजनीतिक परिवर्तन अंततः वहां की जनता पर निर्भर करेगा। सोमवार को क्षेत्रीय संघर्ष के 11वें दिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य कमान केंद्र पहुंचे नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल का अभियान ईरानी नेतृत्व को कमजोर कर रहा है। नेतन्याहू ने कहा, ''हमारी आकांक्षा ईरानी जनता को तानाशाही शासन से मुक्ति दिलाना है; अंततः यह उसी पर निर्भर है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब तक की गई कार्रवाइयों के माध्यम से हम उनकी हड्डियां तोड़ रहे हैं और हम अब भी अभियान जारी रखे हुए हैं।''

ईरान से युद्ध जल्द समाप्त होने की संभावना, लेकिन

तेल आपूर्ति बाधित हुई तो और कठोर हमले करेंगे : ट्रंप

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

दुबई/एपी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि ईरान के खिलाफ युद्ध अल्पकालिक हो सकता है, लेकिन उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर इस्लामी गणराज्य वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित करता है तो लड़ाई और तेज हो सकती है।

ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के मारे जाने के बाद उनके पुत्र अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई को उनका उत्तराधिकारी चुना गया। इसके एक दिन बाद ही तेल की कीमतें कुछ समय के लिए 2022 के बाद के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं।

निवेशकों का मानना है कि यह इस बात का संकेत है कि अमेरिका और इजराइल द्वारा शुरू किए गए युद्ध के 10 दिन बाद ईरान अपनी स्थिति और मजबूत कर रहा है।

हालांकि बाद में कीमतों में थोड़ी नरमी आई, जिसके बाद अमेरिकी शेयर बाजार में तेजी आई और यह उम्मीद जगी कि संभवतः ईरान के साथ युद्ध ज्यादा समय तक नहीं चलेगा।

ट्रंप ने मियामी के पास अपने गोल्फ क्लब में रिपब्लिकन सांसदों से कहा, ''हम कुछ शैतानी ताकतों को खत्म करने के इरादे से कुछ समय के लिए पश्चिम एशिया में थे और मुझे उम्मीद है कि यह सब जल्द खत्म हो जाएगा।''

कुछ घंटे बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया: ''अगर ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल के प्रवाह को रोकने वाला कोई भी कदम उठाता है तो अमेरिका उस पर अब तक की तुलना में बीस गुना अधिक जोरदार हमले करेगा।''

ईरान के सरकारी मीडिया में ट्रंप की टिप्पणियों के प्रकाशन के बाद सीधा जवाब देते हुए अर्द्धसैनिक बल 'रिवोल्यूशनरी गार्ड' के प्रवक्ता अली मोहम्मद नाइनी ने कहा ''ईरान तय करेगा कि युद्ध कब खत्म करना है।''

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान युद्ध की शुरुआत में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की विचारधारा उनसे कुछ अलग थी, हालांकि उन्होंने दोनों के बीच मतभेद की बात को सिरे से खारिज कर दिया।

सोमवार को अपने गोल्फ क्लब में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वेंस शायद युद्ध में जाने को लेकर उतने उत्साहित नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हवाई हमले शुरू करने का उनका फैसला जरूरी था।

सरकार ने गैस आवंटन में बदलाव किया: एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी को मिलेगी प्राथमिकता

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं और परिवहन क्षेत्र के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक गैस के आवंटन में बदलाव किया है। इसके तहत एलपीजी उत्पादन, सीएनजी और पाइप से मिलने वाली रसोई गैस (पीएनजी) को अन्य सभी क्षेत्रों पर प्राथमिकता दी जाएगी।

पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण भारत की एक–तिहाई गैस आपूर्ति बाधित होने के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना जारी कर गैर–प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को मिलने वाली गैस प्रमुख उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।

भारत अपनी 19.1 करोड़ मानक घन मीटर प्रतिदिन गैस खपत का लगभग आधा हिस्सा आयात के जरिये पूरा करता है। होर्मुज जलडमरूमध्य से टैंकर की आवाजाही रुकने के कारण पश्चिम एशिया से आने वाली करीब छह करोड़ मानक घन मीटर प्रतिदिन की गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है। बची हुई तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) को नए सिरे से प्राथमिकता के आधार पर आवंटित किया गया है ताकि एलपीजी उत्पादन, सीएनजी और पीएनजी की मांग का 100 प्रतिशत, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की 80 प्रतिशत और उर्वरक इकाइयों की 70 प्रतिशत जरूरत पूरी की जा सके। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हम स्थिति पर

मिनट–दर–मिनट नजर रख रहे हैं और बदलती जरूरतों को लेकर सतर्क हैं। प्रमुख क्षेत्रों की समूची मांग पूरी करने के लिए अभी गैस आवंटन को नए सिरे से प्राथमिकता दी गई है।

यह आवंटन मुख्य रूप से एलपीजी आपूर्ति बढ़ाने के लिए किया गया है, जो पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण रसोई गैस की लगभग आधी आपूर्ति प्रभावित होने के बाद दबाव में आ गई है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, ''हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि घरेलू उपभोक्ताओं को सीएनजी और पीएनजी की शत–प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित हो और युद्ध की स्थिति के बावजूद अन्य उद्योगों को उनकी आपूर्ति का 70 से 80 प्रतिशत मिलता रहे।'' उन्होंने कहा, ''हम अपने घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कोई कमी नहीं है और घबराने का कोई कारण नहीं है।''

सोमवार देर रात जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी नवीनतम आदेश एलएनजी की बिक्री से संबंधित सभी लंबित अनुबंधों और अन्य वाणिज्यिक समझौतों को रद्द कर देगा। अधिसूचना में कहा गया है कि इससे बची हुई गैस का आवंटन पिछले छह महीनों के वास्तविक औसत उपयोग

मोदी 13 मार्च को गुवाहाटी से पीएम-किसान की 22वीं किस्त के 19,000 करोड़ रुपए जारी करेंगे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13 मार्च को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम–किसान) योजना के तहत 22वीं किस्त का डिजिटल रूप से अंतरण करेंगे। इसके माध्यम से 9.32 करोड़ किसानों को लगभग 19,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। यह कार्यक्रम असम के गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा।

फरवरी, 2019 में शुरू की गई इस योजना के तहत सरकार प्रत्येक पात्र किसान को तीन

किस्तों में सालाना 6,000 रुपए प्रदान करती है। खरीफ फसलों की बुवाई के सत्र से ठीक पहले जारी होने वाली इस राशि से किसानों को बीज, उर्वरक और कीटनाशकों जैसे आवश्यक कृषि आदान जुटाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 'पीटीआई–भाषा' को बताया, प्रधानमंत्री 13 मार्च को गुवाहाटी से पीएम–किसान योजना की 22वीं किस्त की राशि जारी करेंगे। आमतौर पर ये किस्तें फरवरी–मार्च, जून–जुलाई और अक्टूबर के दौरान जारी की जाती हैं। योजना के पिछले आंकड़ों के अनुसार, फरवरी, 2025 में 19वीं किस्त के रूप में 9.8 करोड़ किसानों को 22,000 करोड़ रुपए अंतरित किए गए थे। इसके बाद अगस्त, 2025 में 20वीं किस्त के तहत 9.7 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ रुपए और नवंबर, 2025 में 21वीं किस्त के रूप में नौ करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। 21वीं किस्त तक लगभग 4.09 लाख करोड़ रुपए के कुल वितरण के साथ पीएम–किसान सम्मान निधि कृषि क्षेत्र के लिए सरकार के प्रमुख प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) कार्यक्रमों में से एक बनी हुई है।

मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए नीति बनाएगी गोवा सरकार: मंत्री

पणजी/भाषा। गोवा सरकार के वन मंत्री विश्वजीत राणे ने मंगलवार को कहा कि केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों द्वारा अपनाए गए मॉडल का अध्ययन करने के बाद मानव–वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन नीति तैयार की जाएगी। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष यूरी अलेमाओ के एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने यह बात कही। मंत्री ने कहा कि उन्हें इस समस्या की गंभीरता का पता है क्योंकि पैंथर, बायसन, बंदर और तेंदुए जैसे जंगली जानवर मानव बस्तियों में घुस रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि यह एक गंभीर मुद्दा है। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम जंगल क्षेत्रों में सही पारिस्थितिकी तंत्र बनाएं ताकि वन्यजीव अपने प्राकृतिक आवास में ही रहें।

हर अग्निवीर के भविष्य की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी: मुख्यमंत्री धामी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

देहरादून/भाषा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को कहा कि अग्निवीरों के भविष्य की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है और उनके लिए वर्दीधारी पदों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में अग्निवीरों के रूप में भर्ती होने वाले कैडेट्स के साथ संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने यह भरोसा दिलाया।

ओपी कंडारी नाम के कैडेट ने पूछा कि सरकार अग्निवीर के रूप में सेवा पूरी करने के बाद उनके रोजगार

की क्या व्यवस्था कर रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने वर्दीधारी (राज्यस्तरीय बलों) पदों पर अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की है जबकि इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार भी अनेक क्षेत्रों में अग्निवीरों को अवसर मुहैया करा रही है। उन्होंने कहा, हर अग्निवीर के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। संवाद के दौरान अग्निवीर कैडेट्स ने मुख्यमंत्री से विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे। यह पूछे जाने पर कि एक सैनिक के बेटे होने के कारण क्या उन्होंने कभी सेना में भर्ती होने के बारे में नहीं सोचा तो धामी ने कहा कि अपने पिता के साथ रहते हुए उन्होंने सेना के अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा को करीब से देखा है। उन्होंने कहा, जिस प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ हमारे सैनिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, उसी भावना से वह प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में उत्तराखंड की जनता की सेवा करने का प्रयास करते हैं। हिमांशु रौतेला ने उनसे प्रश्न किया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते वह अपने परिवार को कैसे समय दे पाते हैं? इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी लोग उनका परिवार हैं और सभी गांव उनके अपने गांव हैं।

पश्चिम एशिया संकट के बीच निर्यातकों को बीमा समर्थन देने पर विचार: गोयल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम एशिया संकट के बीच निर्यातकों को मदद देने के लिए सरकार बीमा समर्थन की नई योजना लाने की संभावना तलाश रही है।

गोयल ने कहा कि इस संबंध में निर्यात ऋण गारंटी देने वाली इकाई ईसीजीसी और अन्य विभागों के साथ परामर्श किया जा रहा है। हम निर्यातकों की मदद के लिए बीमा समर्थन जैसी कुछ नई योजनाएं विकसित करने पर भी विचार कर रहे हैं... इस बारे में ईसीजीसी और अन्य विभागों से चर्चा की जा रही है। एक अंतर–मंत्रालयी समूह पश्चिम एशिया संकट से जुड़े घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है और निर्यातकों के साथ लगातार संपर्क में है। गोयल ने कहा कि सरकार उन निर्यातकों की मदद के उपाय तलाश रही है जिनका माल भेजा जा चुका है लेकिन मौजूदा हालात के कारण उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार चौबीसों घंटे हालात पर नजर रखे हुए है। ईरान और अमेरिका–इजराइल के बीच लगातार जारी हमलों से पश्चिम एशिया में

तनाव बढ़ गया है, जिससे तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। यह संकट भारतीय निर्यातकों के लिए इस लिहाज से अहम है कि भारत के लिए पश्चिम एशिया प्रमुख निर्यात बाजारों में से एक है। इससे पहले गोयल ने 'आहार खाद्य एवं आतिथ्य मेला' को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष निर्यातकों में शामिल होने का लक्ष्य रखना चाहिए। भारत फिलहाल दुनिया का सातवां सबसे बड़ा निर्यातक है। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा अब तक किए गए नौ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय उत्पादों के लिए निर्यात के बड़े अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा, हम अब कनाडा के साथ एक व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे रहे हैं। इसके अलावा पश्चिम एशिया के छह देशों के समूह खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के साथ भी चर्चा शुरू हुई है।

चांदी में 10,975 रुपए का उछाल, सोना भी मजबूत

नई दिल्ली/भाषा। राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में मंगलवार को चांदी की कीमतों में 10,975 रुपए का उछाल आया और यह 2.79 लाख रुपए प्रति किलोग्राम की ऊंचाई पर पहुंच गई। वहीं, सोने की कीमत में 400 रुपए की बढ़ोतरी हुई। यह बढ़ोतरी मज़बूत वैश्विक रुझानों के चलते हुई, क्योंकि डॉलर की कमजोरी ने इस 'सुरक्षित निवेश' वाली परिसंपत्ति की मांग को बढ़ा दिया। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, लगातार तीन दिन की गिरावट के बाद चांदी की कीमत में 10,975 रुपए, या 4.09 प्रतिशत का ज़बर्दस्त उछाल आया। सोमवार के बंद स्तर 2,68,300 रुपए प्रति किलोग्राम के मुकाबले मंगलवार को यह बढ़कर 2,79,275 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पर पहुंच गई। सोने की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत में 400 रुपए, या 0.24 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 1,64,700 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) पर पहुंच गया।

मुंबई हवाई अड्डे पर 22 किलो नशीली दवा 'एटोमिडेट' जब्त

अहमदाबाद/भाषा। गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने मुंबई हवाई अड्डे पर एलोवेरा पाउडर के रूप में छिपाकर मलेशिया भेजी जा रही 22 किलोग्राम दवा 'एटोमिडेट' जब्त की है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि इस दवा को हवाई माल ढुलाई के जरिए अवैध रूप से निर्यात किया जा रहा था। यह जब्ती एटीएस द्वारा इस मामले में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किए जाने के कुछ दिनों बाद की गई है। रविवार को गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सूरत निवासी निकुंज गाधिया, चेतन वावडिया और भौतिक पदमनी के रूप में हुई है। एटीएस के अनुसार, सूचना मिली थी कि कुछ लोग दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों में इस दर्द निवारक दवा का निर्यात कर रहे हैं, जहां स्थानीय कानूनों के तहत इसे मादक या मन:प्रभावी पदार्थ के रूप में माना जाता है। एटीएस के अनुसार, विदेशी बाजारों में यह दवा लगभग 4,000 से 5,000 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम में बेची जा रही थी।

गोवा के समुद्र तटों पर विदेशियों को परेशान करने वाले पर्यटकों के खिलाफ कार्रवाई तेज : मंत्री

पणजी/भाषा। गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खौंटे ने कहा कि राज्य के समुद्र तटों पर सेल्फी के लिए विदेशी पर्यटकों को परेशान करने और अनुचित व्यवहार करने वाले पर्यटकों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। खौंटे ने राज्य विधानसभा को सूचित किया कि गोवा देश और दुनिया भर के पर्यटकों का स्वागत करता है, लेकिन गैर–जिम्मेदाराना व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाल के दिनों में ऐसे मामले देखे गए जब युवा पर्यटक समुद्र तटों पर सेल्फी के लिए विदेशी आगंतुकों के पास गए और कभी–कभी वे ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे वहां का शांत वातावरण प्रभावित होता है। पर्यटन मंत्री ने कहा, ''मैंने इस मामले पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ चर्चा की है और नियम–कानून के क्रियान्वयन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें संबंधित थानों के समन्वय में टीपीयू के माध्यम से समुद्र तटों पर अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को तैनात करना शामिल है।

बिरला के मन में खोट नहीं, उन्हें 'पर्ची' दी जाती है: सावंत

नई दिल्ली/भाषा। शिवसेना (उबाठा) के सांसद अरविंद सावंत ने मंगलवार को लोकसभा में दावा किया कि अध्यक्ष ओम बिरला के मन में खोट नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा उन पर 'पर्ची' के माध्यम से दबाव बनाया जाता है।

बिरला के खिलाफ विपक्ष के संकल्प पर चर्चा में भाग लेते हुए सावंत ने यह भी कहा कि पहले की भाजपा दूसरी थी, जिसमें लोगों को सुना जाता था। उन्होंने कहा, ''मैं व्यथित हूं...व्यक्तिगत रूप से बिरला जी के साथ अच्छे रिश्ते हैं...लेकिन आसन पर मेरी मर्जी नहीं, अधिकार चलेगा। उस अधिकार का हम सम्मान करते हैं।'' दक्षिण मुंबई से लोकसभा सदस्य ने कहा, ''हमने सुमित्रा महाजन को देखा है। 2014 की

भाजपा अलग थी। उस वक्त हम साथ थे। वह डांटती थीं, हमें भी डांटा है। उस डांट में प्यार था।'' सावंत का कहना था, ''हमे नहीं लगता कि बिरला साहब के मन में खोट है। हमने उनके चेहरे पर हंसी देखी है, खुशी देखी है, लेकिन कभी–कभी उनका चेहरा गिरा हुआ देखा है। उनके पास पर्ची आती है।'' बजट सत्र के पिछले चरण में जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सदन में नहीं आए तो लोकसभा अध्यक्ष को 'पर्ची' देकर कहलवाया गया कि उनके कहने पर प्रधानमंत्री सदन में नहीं आए। सावंत ने कहा कि सत्तापक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई, लेकिन उन्हें यह बताना चाहिए कि '2जी' के समय जब भाजपा विपक्ष में थी, तब पूरे सत्र में कार्यवाही नहीं चलने दी गई थी। उन्होंने कटाक्ष किया, ''100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली।'' उनका कहना था, ''हम चाहते हैं कि आप (सत्तापक्ष) बिरला साहब को मुक्त करिये, वह न्यायपूर्ण रहें।'' सावंत ने कहा कि बिरला के प्रति व्यक्तिगत रूप से आदर है, लेकिन ऐसा काम होना चाहिए कि भविष्य में अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं पड़े।

चंडीगढ़ धोखाधड़ी मामले में 645 करोड़ रुपए के दावों का निपटान: आईडीएफसी फर्स्ट बैंक

नई दिल्ली/भाषा। निजी क्षेत्र के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने मंगलवार को कहा कि चंडीगढ़ की एक शाखा में सामने आए धोखाधड़ी मामले से जुड़े दावों का निपटान 645 करोड़ रुपए में कर दिया गया है और इस मामले में कोई अन्य गड़बड़ी सामने नहीं आई है। बैंक ने पिछले महीने बताया था कि चंडीगढ़ स्थित उसकी एक शाखा में हरियाणा सरकार के कुछ खातों से जुड़े मामलों में कुछ कर्मचारियों और अन्य लोगों द्वारा 590 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। बैंक ने शेयर बाजार को दी नवीनतम सूचना में कहा कि पहले इस राशि का आकार 590 करोड़ रुपए रहने का अनुमान था लेकिन बाद में मिले दावों के आधार पर 645 करोड़ रुपए की मूल राशि का भुगतान किया गया है, जो प्रारंभिक अनुमान से 55 करोड़ रुपए अधिक है। बैंक ने कहा कि ये सभी दावे उसी घटना एवं संबंधित शाखा से जुड़े हैं और यह कोई नया मामला नहीं है। इसके साथ ही बैंक ने कहा कि फिलहाल कोई अन्य दावा लंबित नहीं है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने कहा कि वह इस धोखाधड़ी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा और बकाया राशि की वसूली के प्रयास करेगा।

मोदी सरकार की आलोचना करने पर झूठे मुकदमे और जेल : सिसोदिया

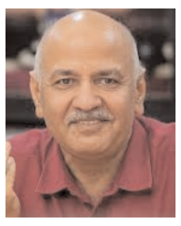

जम्मू/भाषा। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को 'तानाशाही के खिलाफ लड़ाई' जारी रखने की आवश्यकता पर जोर दिया और आरोप लगाया कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले किसी भी व्यक्ति को झूठे आरोपों में फंसाकर जेल भेज दिया जाता है। सिसोदिया ने प्रधानमंत्री से यह स्पष्टीकरण देने की मांग की कि अमेरिका दुनिया के सामने भारत को कैसे 'अपनी कॉलोनी' के रूप में पेश कर रहा है। माता वैष्णो देवी के मंदिर में दर्शन करने के बाद जम्मू–कश्मीर दौरे के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वह जम्मू में अपने मित्र और आम आदमी पार्टी के नेता महराज मलिक के परिवार से मिलने आए हैं। उन्होंने कहा, ''मुझे इस बात का दुख है कि प्रधानमंत्री मोदी के शासन में देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि जब भी कोई आवाज उठाई जाती है, उस व्यक्ति को सीधे जेल में डाल दिया जाता है।''

सहकारी संघवाद कहने के साथ-साथ उस पर अमल भी करना चाहिए : विपक्ष ने रास में कहा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। सरकार पर विपक्ष शासित राज्यों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए राज्यसभा में मंगलवार को विपक्षी दलों के सदस्यों ने दावा किया कि सहकारी संघवाद कहने के साथ साथ उस पर अमल भी करना चाहिए।

ग्रामीण मंत्रालय के कामकाज पर उच्च सदन में हो रही चर्चा में भाग ले रहे तृणमूल कांग्रेस के मोहम्मद नदीमुल हक ने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। उन्होंने कहा कि बढ़–चढ़ा कर आंकड़े पेश करने के बजाय सरकार को असलियत बताना चाहिए। हक ने कहा कि यहां ग्रामीण मजदूर और गरीब लोगों की बात हो रही है और लोग बंगाल में बहुत परेशान हैं क्योंकि उनके नाम मतदाता सूचियों से हटाए जा रहे हैं और उनके हक के लिए राज्य की मुख्यमंत्री सड़कों पर धरने पर बैठी हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले बंगाल को आज कई परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। ''राज्य को उसका बकाया अब तक नहीं मिला है। अदालतों के आदेशों के बावजूद यह स्थिति है। क्या सरकार अदालत के आदेशों की अवमानना कर रही है?'' राज्य के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए हक ने कहा कि मनरेगा से राष्ट्रपिता का नाम ही हटा दिया गया। ''बापू को कौन सम्मान नहीं देता? वह सबके आदरणीय हैं। फिर भी उनके नाम से परहेज क्यों ?'' उन्होंने कहा ''आप रोजगार तो दे नहीं सकते, लेकिन नियम ऐसे बना देते हैं कि लोग वैसे ही परेशान हो जाते हैं। आधार आधारित भुगतान की व्यवस्था का नियम ऐसा ही एक नियम है।'' हक ने दावा किया कि विभिन्न मदों में राज्य का बकाया उसे अब तक नहीं मिल पाया है जबकि राज्य का प्रदर्शन बेहतर रहा है। तृणमूल सदस्य ने कहा कि किसान इसी देश का हिस्सा हैं और उन्हें भी अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए। ''उनकी समस्याएं आज भी वहीं हैं। न आमदनी बढ़ी, न कर्ज माफ हुआ और न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मिली।'' चर्चा में हिस्सा ले रहीं बीजू जनता दल की सुलता देव ने कहा कि ओडिशा एक आदिवासी बहुल राज्य है और वहां की समस्याएं केंद्र के सामने बार बार उठाने के बाद हल नहीं होतीं। ''फिर आप कैसे ग्रामीण विकास की बात करते हैं। आज आदिवासियों से उनके हक छीने जा रहे हैं। उनके लिए अनाज कहां है?''

राहुल गांधी हरियाणा के सोनीपत में किसान की बेटी के विवाह समारोह में शामिल हुए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चंडीगढ़/भाषा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को हरियाणा के सोनीपत जिले के मदीना गांव में एक किसान की बेटी के विवाह समारोह में शामिल हुए।

कांग्रेस के अनुसार, गांधी की मुलाकात किसान संजय से पहली बार 2023 में मदीना गांव में अचानक की गई यात्रा के दौरान हुई थी और उन्होंने उनके साथ खेतों में काम करते हुए किसान परिवारों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों के बारे में जाना था। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सुबह गांव पहुंचे, जहां कांग्रेस के रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और पार्टी के अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया।

सफेद टी–शर्ट और हरी पतलून पहने गांधी ने पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लिया और परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों से बातचीत की। परिवार ने सम्मान स्वरूप उन्हें पगड़ी बांधी। कांग्रेस ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट

किया, ''विपक्ष के नेता राहुल गांधी सोनीपत में किसान संजय मलिक की बेटी के विवाह समारोह में शामिल हुए।'' पार्टी ने पोस्ट में कहा, ''जननायक राहुल गांधी पहली बार संजय जी से 2023 में मिले थे। उन्होंने उनके साथ खेतों में काम किया और किसान परिवारों के संघर्षों की कहानियां सुनीं।'' इस पोस्ट के साथ गांधी की यात्रा की तस्वीरें भी साझा की गई हैं।

पोस्ट में लिखा है, गांधी ने संजय मलिक और उनके परिवार के सुख–दुख में साथ देने का वादा किया था। आज, 'जननायक' उनके परिवार की खुशियों का हिस्सा बने हैं।

इस बीच, विवाह समारोह में गांधी के साथ रहे कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 'एक्स' पर लिखा, ''जिस दौर में बड़े नेताओं में धनाढ्य पूंजीपतियों की शादियों में पहुंचने की होड़ लगी होती है, उसी दौर में राहुल गांधी ने आज उस संजय किसान की बेटी की शादी में पहुंच कर अपना कन्यादान का वचन निभाया जिसके खेत में दो वर्ष पूर्व धान बुआई का कार्य किया था।''

गौरतलब है कि जुलाई 2023 में गांधी ने अचानक मदीना गांव का दौरा किया था और लोगों से बातचीत की तथा खेतों में काम कर रहे किसानों के साथ समय बिताया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने धान की बुआई में हिस्सा लिया, ट्रैक्टर चलाया और खेतों में काम कर रही महिला मजदूरों द्वारा लाया गया भोजन किया था।

भाजपा विधायक दल की बैठक

बेंगलूरु। भाजपा पार्टी विधायकों की एक बैठक मंगलवार को बेंगलूरु में हुई। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष विजयेन्द्र येडीयुरप्पा, विपक्ष के नेता आर अशोक, चलुवाडी नारायणस्वामी और दोनों सदनों के विधायक बैठक में शामिल हुए।

सिद्दरामय्या ने वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कमी पर केंद्र से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने मंगलवार को बेंगलूरु में होटलों एवं रेस्त्रां को पर्याप्त वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आपूर्ति बहाल नहीं की गई, तो शहर के होटल, रेस्त्रां और कैटरिंग व्यवसाय संचालन बंद करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिससे उन छात्रों और कामकाजी पेशेवरों पर असर पड़ेगा जो नियमित भोजन के लिए इन सेवाओं पर निर्भर हैं।

सिद्दरामय्या ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को लिखे पत्र में तेल विपणन कंपनियों को उचित दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया, ताकि मौजूदा आपूर्ति संकट को दूर किया जा सके और स्थिति में सुधार हो। उन्होंने नौ मार्च को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी आदेश का उल्लेख किया, जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता देने की बात कही गई थी।

उन्होंने बताया कि शहर के कई होटल और रेस्त्रां संघों ने रिपोर्ट किया है कि वे वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और कई प्रतिष्ठान यह चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि यदि आपूर्ति जल्द बहाल नहीं हुई तो उन्हें अस्थायी रूप से अपने कारोबार को बंद करना पड़ सकता है। इस बीच, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि एलपीजी रिफिल की कमी राज्य में गंभीर चिंता का विषय बन गई है। उन्होंने यह भी बताया कि होटलों के मालिकों ने चेतावनी दी है कि यदि आपूर्ति जल्द सुधरी नहीं, तो उन्हें अपने संचालन को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

उपमुख्यमंत्री ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि एलपीजी की कमी के मुद्दे पर संसद में चर्चा की जानी चाहिए और सांसदों से इसे उठाने का आग्रह किया, क्योंकि इस कमी का प्रभाव व्यवसायों और आम जनता दोनों पर पड़ रहा है। उपमुख्यमंत्री ने भाजपा के सांसदों की आलोचना करते हुए कहा कि एलपीजी की कमी के बावजूद वे होटलों और कैटरिंग व्यवसायों जैसे प्रभावित व्यवसायों के मुद्दे पर चुप हैं। उन्होंने कहा कि होटलों ने पहले ही घटती आपूर्ति के कारण अपने संचालन को सीमित करना शुरू कर दिया है।

शिवकुमार ने कहा, अब गैस की कीमतों में बढ़ोतरी और गैस की कमी के कारण लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के सांसद इसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। वे कई अन्य मुद्दों पर अपनी आवाज उठाते हैं-यह अजीब बात है-लेकिन इस पर चुप हैं। उन्होंने ईंधन की बढ़ती कीमतों की ओर भी इशारा करते हुए कहा कि डीज़ल की कीमतों में हाल ही में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे व्यवसायों पर और दबाव बढ़ गया है।

यात्रियों की सुरक्षा के लिए अटूट प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा आरपीएफ

विभिन्न अभियानों में हासिल कीं कई उपलब्धियां

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

हुब्बल्ली। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) यात्रियों की सुरक्षा के लिए अटूट प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। उसने फरवरी में विभिन्न अभियानों में कई सराहनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। आरपीएफ ने 'नन्हे फ़रिश्ते' मिशन के तहत देखभाल और सुरक्षा की जरूरत वाले 50 बच्चों (38 लड़के, 12 लड़कियां) को उनके परिवारों से मिलाया। ये बच्चे विभिन्न कारणों से अपने परिवारों से बिछड़ गए थे।

इसी तरह, उसने ऑपरेशन डिग्निटी के तहत एक बुज़ुर्ग महिला को उचित सत्यापन के बाद उसके परिवार को सौंपा।

उसने 'मेरी सहेली' पहल के तहत अकेली और असहाय महिला यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की। उनकी सीट की जानकारी स्टेशन आरपीएफ टीमों के साथ साझा की गई। गंतव्य स्टेशनों पर प्रतिक्रिया भी ली गई। वर्तमान में, इस पहल के तहत 32 ट्रेनें शामिल हैं।

आरपीएफ ने ऑपरेशन 'उपलब्ध' के तहत यात्रियों को ट्रेन टिकटों की निष्पक्ष उपलब्धता सुनिश्चित करने और काला बाज़ारी को रोकने के लिए कर्नाटक और गोवा में विभिन्न ट्रैवल एजेंसियों और स्थानों पर सघन जांच की। इस दौरान, 23 मामलों में रेलवे अधिनियम की धारा 143 के तहत 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुल 48 सक्रिय टिकटों जिनकी कीमत 77,804 रुपए थी और 65 प्रयुक्त टिकटों जिनकी कीमत 97,496 रुपए थी, को जब्त किया गया।

आरपीएफ ने लाखों रुपए के मादक पदार्थों को जब्त कर संबंधित विभागों को सौंपा। 58 अवसरों पर यात्रियों की गुम या भूली गईं चीजों, जैसे लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, आभूषण और अन्य व्यक्तिगत सामान, जिनकी कीमत 44.8 लाख रुपए थी, को बरामद किया और उनके सही मालिकों को वापस किया।

अतिरिक्त महाप्रबंधक पी अनंत ने आरपीएफ के कर्मियों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने अथक प्रयासों के साथ अपना कर्तव्य निभाया और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की।

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने मंगलवार को बेंगलुरु में कर्नाटक विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अपना संबोधन दिया।

नौवीं कक्षा के छात्र ने छात्रावास में किया हमला, एक की मौत, कई घायल

बल्लारी। कर्नाटक के बल्लारी में एक निजी आवासीय विद्यालय में नौवीं कक्षा के एक छात्र ने लोहे की छड़ और धारदार वस्तु से हमला कर एक व्यक्ति की कथित तौर पर हत्या कर दी और कई अन्य को घायल कर दिया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि शनिवार रात हुई इस घटना के बाद से फरार चल रहे छात्र को सोमवार को शहर के बाहरी इलाके से पकड़ लिया गया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, हमने लड़के को हिरासत में ले लिया है और फिलहाल उसकी काउंसलिंग की जा रही है। तय प्रक्रिया के अनुरूप डॉक्टरों का एक पैनल उसका चिकित्सकीय परीक्षण कर रहा है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि घटना के सटीक कारण का अभी पता नहीं चल पाया है।

पुलिस के मुताबिक, शनिवार रात स्कूल के छात्रावास में नौ छात्र सामाजिक विज्ञान के शिक्षक, जो छात्रावास के वार्डन भी हैं, की निगरानी में थे। आरोप है कि छात्र ने गुस्से में आकर सभी पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि सात अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि रात के भोजन के बाद छात्र छात्रावास में सो रहे थे, तभी आरोपी ने अपने साथियों पर लोहे की छड़ और धारदार वस्तु से हमला कर दिया। सूत्रों ने आशंका जताई कि यह घटना किसी मामूली विवाद का नतीजा हो सकती है। पुलिस ने बल्लारी के ब्रूसपेट थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दो जिलों के बाहर 'कंबाला' आयोजित करने के खिलाफ दायर याचिका शीर्ष अदालत में खारिज

बेंगलूरु/नई दिल्ली/दक्षिण भारत। उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों के अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में 'कंबाला' (भैंसों की दौड़ प्रतियोगिता) के आयोजन के खिलाफ दायर याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने सवाल किया कि इसे राज्य के केवल एक खास क्षेत्र तक ही क्यों सीमित रखा जाए।

कर्नाटक में नवंबर से मार्च के बीच आयोजित होने वाली कंबाला दौड़ में एक जोड़ी भैंसों को हल से बांधा जाता है और उन्हें एक व्यक्ति नियंत्रित करता है। उन्हें कीचड़ भरे समानांतर ट्रैक पर दौड़ाया जाता है, और सबसे तेज दौड़ने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाता है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ''पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) इंडिया'' द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पेटा ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 14 नवंबर के आदेश को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने राज्य को दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों के बाहर किसी भी स्थान को कंबाला आयोजन के लिए अधिसूचित करने से रोकने की मांग खारिज कर दी थी।

न्यायमूर्ति मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा, यदि वे राज्य के अलग-अलग हिस्सों में अपनी संस्कृति को प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो इसमें क्या गलत है? राज्य के अन्य हिस्सों के लोगों को भी इस संस्कृति से परिचित होने दीजिए। इसे केवल किसी एक क्षेत्र तक ही क्यों सीमित रखा जाए? पेटा इंडिया की ओर से पेश वकील ने शीर्ष अदालत में राज्य सरकार द्वारा पहले दायर किए गए एक हलफनामे का हवाला दिया। तब शीर्ष अदालत कंबाला से ही संबंधित याचिकाओं पर विचार कर रही थी।

वकील ने कहा कि उस हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा था कि यह कर्नाटक के दो तटीय जिलों में पारंपरिक खेल है। वकील ने दलील दी, ''इसका बेंगलूरु की परंपरा और संस्कृति से कोई संबंध नहीं है।''

मदुरै हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने को मंजूरी

मदुरै/नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को तमिलनाडु के मदुरै हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय मदुरै के लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए ने कहा कि मदुरै हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के नीतिगत निर्णय से दुनिया के विभिन्न हिस्सों से इस मंदिरों के शहर को हवाई संपर्क प्राप्त करने में मदद मिलेगी और इसके आसपास स्थित विशाल औद्योगिक संकुल को भी लाभ होगा।

भारतीय स्टेट बैंक
आर.ए.सी.पी.सी.- सेक्टर बी, निकट राम राम बैंक चौराहा, अलीगंज, लखनऊ

कब्जा नोटिस (अचल सम्पत्ति)

यद्यपि प्राधिकृत अधिकारी **भारतीय स्टेट बैंक, आर.ए.सी.पी.सी.** द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुनः संरचना तथा प्रतिभूति हित का प्रभावीकरण अधिनियम, 2002 (अधिनियम नं. 54, 2002) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 की धारा-13(12) के सहपठित नियम 9 के अन्तर्गत निम्नलिखित खातेदार को उनके सम्मुख अंकित तिथि को नोटिस जारी कर उनसे 60 दिनों के अन्दर नोटिस में वर्णित राशि तथा ब्याज व अन्य खर्चों सहित अदा करने की मांग की थी।

ऋणी द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने के कारण ऋणी/जमानतदारों और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के सहपठित नियम 9 के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न वर्णित खातों में बंधक सम्पत्ति का उनके सम्मुख अंकित तिथि को कब्जा प्राप्त कर लिया है।

ऋणी/जमानतदारों को विशेष रूप से और आम जनता को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे इस सम्पत्ति के सम्बंध में किसी भी प्रकार का सौदा/व्यवहार **भारतीय स्टेट बैंक, आर.ए.सी.पी. सी.** के अतिरिक्त किसी अन्य से न करें। ऐसा कोई भी सौदा व्यवहार **भारतीय स्टेट बैंक** को देय राशि व तत्सम्बंधित ब्याज, जैसा कि खाते में उल्लिखित किया गया है, के अधीन हो। सम्पत्तियों का विवरण जिसका कब्जा लिया गया है :-

क्र. सं.	ऋण-ग्रहिता का नाम एवं पता / खाता सं. / शाखा	बंधक अचल सम्पत्तियों का विवरण	बकाया धनराशि 13(2) के अनुसार	मांग सूचना की तिथि / कब्जा तिथि
1.	**ऋणी : श्रीमती अंशिका तिवारी पत्नी श्री परिवेश धारीवाल** निवासी 592 Jha/294, रथीन्द्र नगर, तेलीबाग, लखनऊ 226029 **खाता सं.: 40664889234, 40664887157** व **42159362286** **शाखा : RDSO (13427)**, लखनऊ	फ्लैट-003, भूतल, ब्लॉक ए अल्मेरिया विंग 2 AHAD एक्सेलेंसिया सर्वे सं.-58/1, 59/4 व 60 चिक्कनयाकनहल्ली, वार्थर होबली, बैंगलोर-560035, कुल संपत्ति **क्षेत्रफल 1434 वर्ग फीट या सुपर फीट या 133.19 वर्ग मी., जिसका सुपर बिल्ट अप कार्पेट एरिया 1018.45। वर्ग फीट या 94.62 वर्ग मी., कवर्ड एरिया 134.34 वर्ग मी.** है, **चौहद्दीः- पूर्वः** सर्वे सं. 58/2 की भूमि, **पश्चिमः** सर्वे सं. 59/3 की भूमि, **उत्तरः** सर्वे सं. 61 व 62 की भूमि, **दक्षिणः** सड़क व सर्वे सं. 50 की भूमि	**₹ 92,58,230.00** दिनांक **10.12.2025** तक + ब्याज व अन्य खर्चे	09.12.2025 / 07.03.2026

दिनांक : 11.03.2026 स्थान : लखनऊ **प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक**

बेल्लारी दावणगेरे पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड

(पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार का एक उद्यम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
दक्षिणी क्षेत्र-II, क्षेत्रीय मुख्यालय, सिंगनायकनहल्ली, येलहंका होबली, बेंगलुरु-5600064

सार्वजनिक सूचना

बेल्लारी दावणगेरे पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-9, कुतुब इंस्टिट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली, भारत -110016 में है), बिजली के पारेषण के लिए बिजली की लाइनें या विद्युत संयंत्र लगाने के लिए या सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या इस प्रकार स्थापित या अनुरक्षित किए जाने वाले टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए टेलीग्राफ लाइनें और पोस्ट लगाने के संबंध में **दूरसंचार अधिनियम, 2023 (पहले भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885)** के तहत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास निहित कार्यों के उचित समन्वयन के लिए टेलीफोन या टेलीग्राफिक संचार के प्रयोजन हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के तहत सभी शक्तियों को प्रदान करने के लिए भारत सरकार को आवेदन करना चाहता है, और निम्नलिखित पारेषण योजनाओं के लिए सर्वेक्षण, निर्माण, स्थापना, निरीक्षण, निर्माण और अन्य कार्यों के बाद कमीशन, संचालन, रखरखाव और अन्य कार्य करेगा।

पारेषण योजना का नामः दावणगेरे (0.25 गीगावाट) और बेल्लारी (2.75 गीगावाट) में अतिरिक्त आरई क्षमता को जोड़ने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करना।

इस योजना के तहत शामिल कार्य :

क्र. सं.	पारेषण योजना का दायरा
1.	दावणगेरे पीएस में 2X1500 एमवीए, 765/400 केवी आईसीटी (6ठी और 7वीं) द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता में वृद्धि • 765/400 केवी, 1500 एमवीए, आईसीटी – 2 नग • 765 केवी आईसीटी बे – 2 नग • 400 केवी आईसीटी बे – 2 नग • 400 केवी बस सेक्शनलाइजरः 1 सेट
2.	आरई जेनरेशन प्रोजेक्ट्स की डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइनों के टर्मिनेभान के लिए दावणगेरे पीएस में 220 केवी लाइन बे के 4 नग और 400 केवी लाइन बे का 1 नग • 400 केवी लाइन बे – 1 नग • 220 केवी लाइन बे – 4 नग
3.	बेल्लारी पीएस का 400/220 केवी, 6X500 एमवीए आईसीटी तक आगमेंटेभान • 400/220 केवी, 500 एमवीए, आईसीटी – 6 नग • 400 केवी आईसीटी बे – 6 नग • 220 केवी आईसीटी बे – 6 नग • 220 केवी बस सेक्शनलाइजरः 2 सेट • 220 केवी बस कपलर (बीसी) बे – 2 नग • 220 केवी ट्रांसफर बस कपलर (टीबीसी) बे – 2 नग
4.	बेल्लारी – दावणगेरे दूसरी 400 केवी (क्वाड) डी/सी लाइन • 400 केवी लाइन बे – 2 नग (बेल्लारी पीएस पर) • 400 केवी लाइन बे – 2 नग (दावणगेरे / चित्रदुर्ग पीएस पर)
5.	आरई डेवलपर्स की डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइनों के टर्मिनेशन के लिए बेल्लारी पीएस पर 220 केवी लाइन बे के 5 नग। • 220 केवी लाइन बे – 5 नग।

I योजना के अंतर्गत शामिल बेल्लारी – दावणगेरे द्वितीय 400 केवी (क्वाड) डी/सी लाइन निम्नलिखित गांवों, कस्बों और शहरों से होकर, उनके ऊपर, चारों ओर और उनके बीच से गुजरेगी :

राज्यः कर्नाटक

गांवों के नाम	तालुक	जिला
अडाविमल्लनकेरे (अडावि मल्लनकेरी), अडाविमल्लनकेरे थांडा, वरकनहल्ली (वरकनाहल्ली), सोगी (सोगे), नंदीहल्ली (नंधीहल्ली), मुसुवनकल्लाहल्ली (मुसुकिना कल्लाहल्ली), महाजनदाहल्ली (महाजनधहल्ली), उत्तांगी (उत्थांगी), होलागुंधी (होलागुंधा), भाविहल्ली, तलकल्लू, सिद्धेश्वरा मंदिर (सिद्धेश्वरा देवालय), मुदेनुरु (मुधेनुरु), इट्टिगी	हुविना हाडागल्ली (हुविना हाडागली, हाडागली)	विजयनगरा
हनुमगोंडानहल्ली (बोदिगेरहल्ली), मोरागेरी (मुरुगेरी),	हगारीबोम्मनहल्ली	विजयनगरा
कणिवेहल्ली (कणिविहल्ली), अनाजीगेरे (अनाजिगेरी), मादिहल्ली, होसाकोटे, कोंगाना होसुरु, नंदीबेवुरु, नंदीबेवुरु थांडा, कोमारनहल्ली, अडविहल्ली (अडिविहल्ली), अरसीकेरे (अरसीकेरी), बुदिहालू, सासविहल्ली (ससविहल्ली), मुत्तिगी, मुत्तिगी हल्ला, निलुवंजी (निलवनजी), मत्तिहल्ली, जोइसलिंगपुर (जोशीलिंगपुरा), कडबागेरे (कडबागेरी), हगरीगुडीहल्ली (हगरी गूदिहल्ली), पृथ्वीश्वरा (पलथेश्वरा), बेण्णिहल्ली (बेण्णेहल्ली), निच्छापुर (निच्छापुरा), चिगटेरी, मैदुरू (मैदुरू), कोंगना होसुरु वन सं. 1, जाजीकलगुड्डा आरक्षित वन, जाजीकलगुड्डा कणिविहल्ली, चिगटेरी हिल ब्लॉक सं. 4, मैदुरू हिल ब्लॉक सं. 3, स्रींगारा थोटा (श्रृंगारथोटा) हिल ब्लॉक सं. 7, सिंगाराथोटा (स्रींगारा थोटा, श्रृंगारथोटा), निच्छापुरा हिल ब्लॉक सं. 6, कोमारनहल्ली वन ब्लॉक सं. 2, जिट्टिनकट्टी (जित्तिनकट्टी) उत्तर आरक्षित वन, निच्चाव्वानाहल्ली (निच्चावनाहल्ली), हिक्किमगेरी (हिक्किमगेरा), भाविहल्ली, होसा ओबालापुर (होसा ओबालापुरा), हुनासिहल्ली, कसवनहल्ली, कुणेमादिहल्ली, लोलेश्वरा, तिप्पनहल्ली, हले ओबालापुर (हले ओबालापुरा), चिक्का कब्बाली, गुडीहालु, केरेगुडीहल्ली, कोड्कोल्ला, बसवना गुड़ी, चिक्का हगारी आर (चिक्का हगारी नदी), तिम्मलापुर, करडी गुड्डा	हरपनहल्ली (हरपनहल्ली)	विजयनगरा
बसवनकोटे, सिद्दयानकोटे (सिद्दैयानकोटे), उज्जप्पावडेरहल्ली, वरविनाहल्ली, उच्चंगीपुर (उच्चंगीपुरा), गुड्डानाइकनहल्ली, उरलाकट्टे, दिदि्दगे, केंचम्मनहल्ली (केंचम्मनागथिहल्ली), बड़ाबसवनहल्ली, असगोडु, अंकलाहल्ली, राजापुरा, पल्लागट्टा (पल्लागट्टे), गोडे, ओबालापुर (ओबालापुरा), मसानिकट्टे, कुलमगट्टा, मरिकुंटे, कल्लेण हल्ली, लिंगनहल्ली (लिंगन्ननहल्ली), सुरगोंडानहल्ली (सोरागोंडानहल्ली), काटेनहल्ली (काचेनहल्ली), पालनायकनकोटे (पालनाइकनकोटे), मिनिगरहल्ली (मीनिगरहल्ली), मेदिकेरिहल्ली (मेदेकेरेहल्ली, मेदाकेरेनाहल्ली), मदनहल्ली, बोरापुरा, मुश्टीगरहल्ली (मुस्तीगरहल्ली), नरेनाहल्ली, अज्जीबोम्मनहल्ली, (अज्जाम्मोमानाहल्ली) सुरड्डीहल्ली (सुरेड्डीहल्ली), कोडादागुड्डा (कोड़ाथागुड्डा), बसवपुर (बूदीगुप्पे बसवपुरा), चेन्नापुरा, हिरे अरीकेरे (हिरे अराकेरे), देवीकेरे, चिक्का अरीकेरे (चिक्काराकेरे), हलवादंडी, सेट्टीगुंडनहल्ली (शेट्टीगोंडानहल्ली), मदागिनकेरे (मेदागिनकेरे), बग्गेनहल्ली, रास्ते माचिकेरे (रास्तेमाचिकेरे), व्यासगोंडानहल्ली (वैश्यगोंडानहल्ली), कस्तूरीपुरा, बुल्लनहल्ली, गोपागोंडानहल्ली, कुल्लोबनहल्ली, कोराटिकेरे (कोराटागेरे), गुत्तीदुर्गा, सोमनहल्ली, संते मुद्दापुरा (संतेमुद्दापुरा), बिस्तुवल्ली, रास्ते मकुंटे (रास्तेमकुंटे), कट्टिगेहल्ली, गोलारहट्टी, लंबानीहट्टी, महाराजारहट्टी, होसुरु, वड्डारहट्टी, उद्दबोरनहल्ली, रंगय्यानदुर्गा आरक्षित वन।	जगलूर (जगलूरु)	दावणगेरे (दावणागेरे)

रूट अलाइनमेंट की प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध है। आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि मार्च 11, 2026 से दो महीने के भीतर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तावित ट्रांसमिशन सिस्टम पर अपना विचार/प्रतिनिधान लिखित में दें।

अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संपर्क करें :

नामः बी. श्रीधर
पदः वरिष्ठ महाप्रबंधक (परियोजना प्रभारी)
कार्यालय का पताः बेल्लारी दावणगेरे पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
(पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार का एक उद्यम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
दक्षिणी क्षेत्र-II क्षेत्रीय मुख्यालय, सिंगनायकनहल्ली, येलहंका होबली, बेंगलुरु-560064.
ईमेल पताः bsridhar@powergrid.in, **कार्यालय फोन नंबरः** 080-23093700, **मोबाइल नंबरः** 9449596035

SR-II/PR-11/PBN/2025-26/Adfactors

राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बनाएं कार्ययोजना : शर्मा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के विकास कार्यों को गति देने और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सुदृढ़ राजस्व व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार राजस्व संग्रहण को मजबूत करने के साथ-साथ पारदर्शी और सरल कर व्यवस्था विकसित करने की दिशा में लगातार कार्य रही है। शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीति, खनन ब्लॉक्स की नियमित नीलामी, पारदर्शी कर व्यवस्था सहित विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं जिससे गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष समान अवधि में राज्य सरकार को 7.10 प्रतिशत की राजस्व अर्जन में वृद्धि हुई है। शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न विभागों द्वारा राजस्व संग्रहण के संबंध में बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिकारी राजस्व आय में वृद्धि के लिए कार्ययोजना बना कर कार्य करें। साथ ही, सभी विभागों की राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक समिति का भी गठन किया जाए जो नियमित तौर पर विभागवार प्रगति का आकलन करे। शर्मा ने कहा कि जीएसटी सुधारों से आमजन को राहत मिली है और इस क्षेत्र में डेटा एनालिटिक्स में प्रदेश देशभर में अग्रणी है तथा इससे करदाताओं को भी लाभ मिला है। शर्मा ने कर चोरी और पारदर्शी कर व्यवस्था के लिए सुदृढ निगरानी तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए। साथ ही, कर संबंधी सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराने के लिए इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम के प्रभावी उपयोग पर भी जोर दिया। अधिकारियों ने बताया कि इस सिस्टम के उपयोग करने से करदाताओं को अधिक सुगमता हुई है। राज्य में जीएसटी संग्रहण में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से परिवहन विभाग द्वारा भी गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 9.51 प्रतिशत अधिक राजस्व अर्जन हुआ है। साथ ही, ग्रीन टैक्स से आय में भी वृद्धि हुई है। शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही, व्हीकल स्क्रैपिंग का भी व्यवस्थित निष्पादन किया जाए।

बैठक में बताया गया कि पंजीयन एवं मुद्रांक द्वारा डीएलसी दरों में किए गए सुधारों से इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में स्टांप ड्यूटी से अर्जित राजस्व समान अवधि में 16.34 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं खनन पट्टों की नीलामी से राजस्व अर्जन पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 12 प्रतिशत बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विभाग द्वारा अवैध खनन पर पूर्ण रोकथाम के उपाय किए जाएं तथा इस कार्य में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही, उन्होंने पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग को संपत्तियों के पंजीयन की प्रक्रिया सरल करने और आमजन को अधिक से अधिक राहत पहुंचाने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने राज्य में अवैध शराब की बिक्री पर भी प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए। बैठक में आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आबकारी नीति में किए गए नीतिगत सुधारों से इस वर्ष आबकारी से राजस्व पिछले वित्तीय वर्ष से लगभग 7.52 प्रतिशत अधिक रहा है। बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

'चिरंजीवी योजना' में बदलाव से गरीब मरीज भटकने को मजबूर : अशोक गहलोत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि उनके कार्यकाल की 'चिरंजीवी योजना' में किए गए बदलाव के कारण बजट की कमी और कुप्रबंधन पैदा हो गया है, जिससे गरीब मरीज दर-दर भटकने को मजबूर हैं। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार को चिकित्सा सुविधाओं के प्रति गंभीरता दिखाते हुए नयी बीमा योजना में अविलंब सुधार करना चाहिए, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। गहलोत ने जोधपुर में आयुष्मान आरोग्य योजना के कारण अस्पतालों में मरीजों को हो रही परेशानी संबंधी एक समाचार का उल्लेख करते हुए कहा, जोधपुर के अस्पतालों की यह स्थिति चिंताजनक है। हमारी सरकार की 'चिरंजीवी योजना' का उद्देश्य हर राजस्थानी को इलाज की निश्चिंतता देना था, लेकिन इस योजना में किए गए बदलाव के कारण बजट की कमी और कुप्रबंधन से गरीब मरीज दर-दर भटकने को मजबूर हैं।

उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री विधानसभा में जोधपुर के अस्पतालों की बिगड़ती स्थिति के बारे में मेरे द्वारा लिखे गए पत्र का जिक्र राजनीति के लिए करते हैं, लेकिन समस्याओं के समाधान में उनकी रुचि नहीं दिखाई देती। उनकी सरकार न तो जोधपुर के नए अस्पतालोंदिगाड़ी, प्रतापनगर, चैनपुरा और मगरा पूंजला का निर्माण पूरा होने के बावजूद उन्हें शुरू करवा पा रही है और न ही पुराने अस्पतालों का रखरखाव और संचालन ठीक से कर पा रही है। गहलोत ने राज्य सरकार से इस मामले में गंभीरता दिखाने की मांग करते हुए कहा कि नयी बीमा योजना में जल्द सुधार किए जाएं, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।

रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ने पर सदन में हंगामा, कांग्रेस विधायकों का बहिर्गमन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को घरेलू व वाणिज्यिक रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत बढ़ने का मुद्दा उठा और इस दौरान विपक्षी कांग्रेस ने नारेबाजी की और सदन से बहिर्गमन किया। कांग्रेस विधायक अमित चाचाण ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, सरकार ने महंगाई से आम आदमी की कमर तोड़ने का काम किया है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 60 रुपये व वाणिज्यिक गैस के दाम लगभग 110 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। इससे प्रत्येक परिवार प्रभावित होगा... सरकार न जवाबदेह है और न जिम्मेदार... जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार को 'सब्सिडी' देकर जनता को राहत देनी चाहिए थी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मुद्दे पर सरकार से जवाब देने की मांग की। उन्होंने कहा कि लोग परेशान हैं, होटल, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, ऐसे में सरकार को बताना चाहिए कि वह सिलेंडर के दाम कम करेगी या नहीं? कांग्रेस विधायकों ने कुछ देर नारेबाजी व हंगामा करने के बाद सदन से बहिर्गमन किया।

इससे पहले प्रश्नकाल में भी इस मुद्दे को लेकर जूली व खाद्य मंत्री सुमित गोदारा के बीच नोकझोंक हुई।

एक तारांकित प्रश्न के दौरान जूली ने पूरक प्रश्न पूछते हुए कहा, रसोई गैस के दाम बढ़े हैं ...ऐसे में सरकार सिलेंडर के बढ़े हुए दाम की सब्सिडी अपनी तरफ से देकर राजस्थान की जनता को राहत देना चाहती है या नहीं है।' खाद्य मंत्री गोदारा ने कहा, हमारी सरकार पुरजोर प्रयास कर रही है कि आम लोगों को ज्यादा परेशानी न हो। भारत व राजस्थान सरकार रसोई गैस की कमी नहीं होने देंगी। कांग्रेस विधायकों के हंगामे के बीच अध्यक्ष ने अगला प्रश्न लिया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही आगे बढ़ी।

जयपुर के आमागढ़ किले व अम्बा माता मंदिर का होगा जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण : संजय शर्मा

जयपुर। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि जयपुर शहर के आमागढ़ किले में जाने वाला मार्ग वन क्षेत्र से निकलता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि वन विभाग द्वारा इस मार्ग का संधारण करवाया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार द्वारा आमागढ़ किले तथा यहां स्थित अम्बा माता के मंदिर में जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य भी करवाया जाएगा। वन राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक रामकेश द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अलवर जिले के थानागाजी क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक प्रतापगढ़ के जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण और संधारण के लिए राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष के बजट में प्रावधान किया गया है। इससे पहले सदस्य रामकेश के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि जयपुर शहर के आमागढ़ किले में जाने वाला मार्ग आरक्षित वन खण्ड 92, बन्द की गढ़ी आम्बागढ़ के वन क्षेत्र से निकलता है। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्रों से निकलने वाले रास्तों की मरम्मत और निर्माण कार्य सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त ही करवाये जाने का प्रावधान है।

शर्मा ने कहा कि अम्बा माता जी के मन्दिर में दर्शन के लिए जाने वाली आम जनता को नहीं रोका जाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में विभागीय स्तर पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार व किले की मरम्मत करवाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मिशन 'हरियालो राजस्थान' के तहत आगामी मानसून में 10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राज्य में हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित मिशन हरियालो राजस्थान के तहत आगामी मानसून-2026 में 10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को शासन सचिवालय में विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बैठक आयोजित की गई। मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 से 2028 तक राज्य में कुल 50 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी हितधारक विभाग राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करें तथा नवगठित जिलों के अनुसार जिलावार लक्ष्य निर्धारित कर जिला कलेक्टरों के साथ समन्वय स्थापत करते हुए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि व्यापक पौधारोपण के माध्यम से राज्य में हरित आवरण बढ़ाने, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मिशन हरियालो राजस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि पौधारोपण कार्यक्रम को जनभागीदारी से जोड़ते हुए विभिन्न विभागों, स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थानों तथा स्वयंसेवी संगठनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि इस अभियान को व्यापक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया जा सके।

उन्होंने बताया कि पौधारोपण कार्यक्रम की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए तीन-स्तरीय टास्क फोर्स व्यवस्था बनाई गई है। इसके तहत राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर तथा उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स कार्य करेगी।

उन्होंने बताया कि पौधारोपण कार्यक्रम के लिए विस्तृत समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसके अनुसार 31 मार्च 2026 तक पौधारोपण स्थलों का चयन किया जाएगा। अप्रैल से जून 2026 के दौरान गड्ढे खोदने, फेंसिंग सहित अन्य तैयारियाँ की जाएंगी। 15 जून से 15 जुलाई के बीच नर्सरियों से पौधों की खरीद की जाएगी तथा 1 जुलाई से सितम्बर 2026 तक राज्यभर में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जाएगा। आनंद ने जानकारी दी कि वन विभाग की नर्सरियों में वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 626.10 लाख पौधों की तैयारी की जा रही है, जबकि वन भूमि पर पौधारोपण के लिए अतिरिक्त 200 लाख पौधे तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग पौधारोपण गतिविधियों की जानकारी नियमित रूप से हरियालो ऐप पर अपलोड करें, ताकि कार्यक्रम की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके।

आनंद कुमार ने अवगत कराया कि वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत 7 करोड़ पौधारोपण लक्ष्य के विरुद्ध 7.22 करोड़ पौधे लगाए गए। इसी प्रकार मानसून-2025 में 10 करोड़ लक्ष्य के मुकाबले 11.74 करोड़ से अधिक पौधारोपण कर लक्ष्य से अधिक उपलब्धि प्राप्त की गई।वहीं वर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न विभागों को कुल 10 करोड़ पौधारोपण लक्ष्य आवंटित किया गया है।

बैठक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) पी.के. उपाध्याय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) सुशिखा मेहरा, मुख्य वन संरक्षक (आयोजना) एस.आर.वी. मूर्थी, सदस्य सचिव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल कपिल चंद्रवाल, आईजी होम दीपक कुमार सहित जल संसाधन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, खेल, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, कृषि, उद्यानिकी, ऊर्जा, सार्वजनिक निर्माण, नगरीय विकास एवं आवासन तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ में सड़क निर्माण के प्रगतिरत कार्य जून माह तक पूर्ण होंगे : दिया कुमारी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। उपमुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ - लक्ष्मणगढ़ में दो वर्षों में 96 करोड़ रुपए की लागत से कुल 115 कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 64 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं व 50 कार्य प्रक्रियाधीन है तथा शेष एक कार्य का निरस्तीकरण प्रक्रियाधीन है। उन्होंने आश्वस्त किया कि 19 जून 2026 तक सड़कों के सभी 50 प्रक्रियाधीन कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। उपमुख्यमंत्री प्रश्नकाल में सदस्य मांगेलाल मीना द्वारा इस संबंध में पूरक प्रश्न का जवाब दे रही थीं। उन्होंने कहा कि बजट 2026-27 में विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ - लक्ष्मणगढ़ में 10 करोड़ रुपए के सड़क कार्यों की घोषणा की गई है।

इससे पहले सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए मूल प्रश्नों का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सड़कों के नवीनीकरण के मापदण्ड राज्य सड़क नीति 2013 के अनुसार निर्धारित हैं। उन्होंने इसका विवरण सदन के पटल पर रखा।

उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ में 67 क्षतिग्रस्त एवं नॉन पेचेबल सड़कें थी। जिनमें से 26 सड़कों के कार्यों की स्वीकृति जारी की जा चुकी हैं एवं कार्य प्रगतिरत है। जिसका विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा।

उन्होंने बताया कि बजट घोषणा वर्ष 2026-27 में वर्तमान में प्रदेश की सड़कों के नवीनीकरण व सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता को देखते हुए नॉन पेचेबल व क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 1400 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। घोषणानुसार कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर सड़कों का चयन कर नवीनीकरण करवाया जाना प्रस्तावित है।

पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह और उनकी माता के बीच गृह-कलह की तस्वीरें वायरल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जोधपुर। पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल मंगलवार सुबह जब पुलिस और सुरक्षाकर्मियों के साथ अपने पैतृक निवास पहुंचे, तो वहां हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला।

अपनी ही माता और बेटे के साथ उनकी तीखी बहस के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसे लेकर मारवाड़ की जनता में आक्रोश और दुख दोनों देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे संदेशों में दावा किया जा रहा है कि मानवेंद्र सिंह पुलिस बल लेकर अपने घर पहुंचे, लेकिन सूत्रों और पुलिस विभाग से मिली जानकारी के अनुसार स्थिति कुछ और ही नजर आ रही है: पुलिस विभाग के अनुसार, इस मामले में फिलहाल कोई आधिकारिक मुकदमा या परिवाद दर्ज नहीं हुआ है।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, वीडियो में जो वर्दीधारी दिख रहे हैं, वे आधिकारिक पुलिसकर्मी नहीं बल्कि प्राइवेट सिक्योरिटी के जवान हो सकते हैं, जो संभवतः पूर्व में उनकी सुरक्षा में तैनात रहे हैं। वीडियो में स्व. जसवंत सिंह की 90 वर्षीय पत्नी अपनी दहलीज की रक्षा के लिए अपने पुत्र के सामने खड़ी नजर आ रही हैं। इसे पारिवारिक संपत्ति या मर्यादा से जुड़ा विवाद माना जा रहा है। इस घटना ने मारवाड़ के संस्कारों और 'मां' के सम्मान को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है।

वायरल हो रहे संदेशों में तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं: 90 साल की बुजुर्ग मां आज अपनी तपोभूमि और उस दहलीज की रक्षा के लिए अपने ही पुत्र के सामने चट्टान बनकर खड़ी है। क्या शस्त्रधारी गार्ड मारवाड़ की इस जननी को डरा पाएंगे?

मानवेंद्र सिंह जसोल ने हाल ही में 'सरहद की समृद्धि यात्रा' शुरू की थी, जिस पर भी कई सवाल खड़े हुए थे। आलोचकों का कहना है कि जो अपनी पारिवारिक दहलीज पर संवाद स्थापित नहीं कर पा रहे, वे सरहद की समृद्धि का ब्लू-प्रिंट कैसे देंगे। यह पूरी तस्वीर आज समूचे मारवाड़ को स्तब्ध कर रही है।

वन, पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन का किया निरीक्षण

जयपुर/दक्षिण भारत। राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) आमजन की समस्याओं का अंतिम पड़ाव साबित हो रही है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनन्द कुमार ने मंगलवार को सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उनके विभाग से संबंधित शिकायतों के निस्तारण की प्रगति की जानकारी ली तथा परिवादियों से सीधे संवाद कर मौके पर ही संबंधित अधिकारीयों को प्रकरणों के निस्तारण कर कार्वाई से अवगत कराने के निर्देश दिए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव के परिवादियों से संवाद के दौरान बूंदी जिले के लाखेरी के पंकज सुमन द्वारा बताया गया कि मेन रोड पर लगे पीपल के पेड़ मे से गुजर रही बिजली लाइन आमजन के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने मौके पर ही बूंदी जिला कलक्टर अक्षय गोदारा को फोन कर मंगलावार शाम से पहले परिवादी की समस्या के समाधान कर की गई कारवाई से अवगत कराने के निर्देश दिए। इसी प्रकार सीकर के महेश कुमार खुडानिया ने समस्या के समयबद्ध समाधान हो जाने पर राज्य सरकार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। जयपुर के विष्णु द्वारा दर्ज केमिकल फेक्ट्री से प्रदूषण की शिकायत पर आनंद कुमार ने संबंधित अधिकारी को औचक निरीक्षण कर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए राजस्थान संपर्क पोर्टल समस्याओं का अंतिम पड़ाव होना चाहिए। इसके माध्यम से प्राप्त शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

राजस्थान कृषि उपज मण्डी प्रांगण भूमि अर्जन नीति का किया अनुमोदन, मंडियों और यार्डों का तेजी से होगा विकास : भजनलाल

जयपुर/दक्षिण भारत। प्रदेश की कृषि उपज मण्डियों में आधारभूत सुविधाएं सुदृढ़ करने दिशा में राज्य सरकार निरन्तर महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मण्डी विकास से संबंधित भूमि अर्जन की प्रक्रिया पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए राजस्थान कृषि उपज मण्डी प्रांगण भूमि अर्जन नीति का अनुमोदन किया है। इस नीति से मण्डी समितियों के प्रांगण में आधारभूत संरचनाएं सुदृढ़ होने के साथ ही कृषि उपज के विपणन की व्यवस्था अधिक सुगम बनेगी। नीति के अंतर्गत मण्डी विकास की परियोजनाओं से संबंधित भूमि अवाप्ति के जिन मामलों में अवार्ड जारी हो चुका है, ऐसे प्रकरणों में अवाप्त या अवाप्ताधीन कुल भूमि का 15 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की जाएगी। इसी प्रकार, भूमि अवाप्ति के ऐसे मामलें जिनमें अवार्ड जारी नहीं हुआ है, उन प्रकरणों में 20 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की जाएगी। साथ ही, आपसी समझौते से भूमि के अर्जन पर भू-धारकों द्वारा मण्डी समिति को निःशुल्क नवीन भूमि समर्पित करने पर कुल समर्पित भूमि के बदले 20 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की जाएगी। इस नीति से भूमि अर्जन कर उपयुक्त स्थानों पर नवीन यार्डों का निर्माण तेजी से संभव हो सकेगा। साथ ही, भूमि अवाप्ति से संबंधित लंबित न्यायिक प्रकरणों का निस्तारण भी हो सकेगा। कृषि उपज मण्डी समितियों में 22 करोड़ रूपये से अधिक के विकास कार्यों की दी स्वीकृति मुख्यमंत्री ने राज्य की विभिन्न कृषि उपज मण्डी समितियों के विकास के लिए लगभग 22 करोड़ रूपये से अधिक कार्यों की स्वीकृति प्रदान की है।

मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, झारखंड को जोड़ने वाली रेलवे की दो परियोजनाओं को मंजूरी दी

नई दिल्ली/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पश्चिम बंगाल और झारखंड को जोड़ने वाली रेलवे की दो 'मल्टीट्रैकिंग' परियोजनाओं को मंगलवार को मंजूरी दे दी। इन पर 4,474 करोड़ रुपए की कुल लागत आएगी। ये परियोजनाएं सैंथिया-पाकुड़ और संतरागाछी-खड़गपुर के बीच चौथी रेलवे लाइन से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 'एक्स' पर कहा, ''ये परियोजनाएं पूर्वी भारत में रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगी, दक्षता बढ़ाएंगी, भीड़भाड़ कम करेंगी और इन राज्यों में कनेक्टिविटी मजबूत करेंगी। वे माल ढुलाई में भी सुधार करेंगी, आर्थिक गतिविधि का समर्थन करेंगी और टिकाऊ, कम कार्बन परिवहन को आगे बढ़ाएंगी।'' पश्चिम बंगाल और झारखंड के पांच जिलों को शामिल करने वाली दो परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 192 किलोमीटर तक बढ़ाएंगी।

पर्यावरण मंजूरी मिलने की अवधि को तीन साल से घटाकर तीन महीने किया गया है : भूपेन्द्र यादव

नई दिल्ली/भाषा। पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने अरावली पर्वतमाला की सुरक्षा को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता जताते हुए राज्यसभा में मंगलवार को कहा कि पर्यावरण मंजूरी मिलने को लेकर पहले करीब तीन साल का समय लग जाता था, जिसे नरेन्द्र मोदी सरकार ने घटाकर तीन महीने कर दिया है। उच्च सदन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि जब 2014 में नरेन्द्र मोदी सरकार आयी थी, तब देश में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 757 थी जो आज 2026 में बढ़कर 1134 हो गई है। 2014 में देश में कुल संरक्षित क्षेत्रफल 1,68,838 वर्ग किलोमीटर था जो 2026 में बढ़कर 1,87,162 वर्ग किलोमीटर हो गया। देश में 2014 में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 103 थी जो 2026 में बढ़कर 106 हो गए हैं। यादव ने कहा कि इसी अवधि में वन्य जीव अभयारण्य की संख्या 539 से बढ़कर 574 हो गई हैं। उन्होंने कहा कि जब हम जल, जंगल और जमीन की बात करते हैं तो 2014 में जहां सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र 48 थे जो आज बढ़कर 309 हो गए हैं। पर्यावरण मंत्री ने माना कि पिछले 50 सालों में बाघ संरक्षण को लेकर सभी सरकारों ने अच्छे प्रयास किए। उन्होंने कहा कि 2014 में बाघों की संख्या 2226 थी जो 2026 में बढ़कर 3682 हो गई है।

भदोही में ग्राम प्रधान के बेटे ने चौकीदार को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया, हत्या का मामला दर्ज

भदोही (उप्र)/भाषा। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में ग्राम प्रधान के बेटे ने एक चौकीदार पर कथित तौर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घटना में 80 प्रतिशत तक झुलस जाने के बाद चौकीदार जैसलाल सरोज (55) को गंभीर हालत में वाराणसी के बीएचयू ट्रामा सेंटर भेजा गया था, जहां मंगलवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि घटना सोमवार सुबह यहां ज्ञानपुर थाना क्षेत्र के पीपर गांव में हुई, जब चौकीदार गांव में लगे हैंडपंप के खराब होने पर उसका पाइप बदलवाने के लिए गांव के प्रधान राम नाथ यादव के घर गया था। उन्होंने बताया इस बीच वहां हुई कहासुनी के बाद पूर्वा करीब दस बजे यादव का बेटा कमलेश यादव (30) पेट्रोल लेकर आया और सरोज पर डाल कर आग लगा दी। एसपी ने कहा कि सरोज को जलता देख कुछ गांव वालों ने उस पर कंबल डालकर आग बुझाई, लेकिन तब तक उसका शरीर 80 प्रतिशत से अधिक झुलस चुका था।

ओडिशा: जीजा और साली ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की

बालासोर/भाषा। ओडिशा के बालासोर जिले में 35 वर्षीय व्यक्ति और उसकी साली ने कथित तौर पर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि दोनों के बीच अवैध संबंध होने का संदेह था और 18 वर्षीय युवती गर्भवती थी। पुलिस के मुताबिक, यह घटना सोमवार को जलेश्वर स्टेशन के पास हुई। पुलिस ने बताया कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है।

राहुल एआई सम्मेलन के दौरान हुए विरोध-प्रदर्शन के शिल्पकार

भारत को बदनाम करना चाहते हैं : भारतीय जनता पार्टी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हाल ही में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन के दौरान देश को 'शर्मिंदा' करने के उद्देश्य से किए गए विरोध प्रदर्शन का 'शिल्पकार और डिजाइनर' करार दिया तथा उन पर भारत को अपमानित और बदनाम करने की कोशिश करने का मंगलवार को आरोप लगाया।

भाजपा सांसद एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए युवा कांग्रेस के सदस्यों द्वारा ''इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026'' के दौरान किए गए विरोध प्रदर्शन का जिक्र किया और आरोप लगाया कि यह एक पूर्वनिर्धारित योजना का हिस्सा था। पात्रा ने कहा, ''उस समय हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह कांग्रेस पार्टी का 'अर्द्धनग्न', 'अविवेकी' और शर्मनाक प्रदर्शन' था।'' उन्होंने दावा किया कि यह प्रदर्शन कोई अचानक हुई घटना नहीं, बल्कि पहले से योजनाबद्ध और सोची-समझी हरकत थी। भाजपा नेता ने आरोप लगाया, ''यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक प्रयोग था। हमने

उस समय भी कहा था कि इस हरकत के शिल्पकार और डिजाइनर खुद राहुल गांधी थे और इसकी योजना उनके आवास पर तैयार की गई थी।''

भाजपा नेता ने कांग्रेस की एक बैठक में सोमवार को एआई सम्मेलन को लेकर गांधी द्वारा दिए गए बयान का हवाला देते हुए दावा किया कि नेता प्रतिपक्ष ने (विरोध प्रदर्शन की) जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है। पात्रा ने कहा, ''कल राहुल गांधी ने खुद कहा, 'हां, हमने काम कर दिया।' देश देख रहा था कि जब उन्होंने दावा किया कि उन्होंने भारत में हो रहे एआई शिखर सम्मेलन को 'बाधित' कर दिया, तो उनके चेहरे पर मीर जाफर जैसी एक मुस्कान थी।'' मीर जाफर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना में एक वरिष्ठ अधिकारी था, जिसने नवाब बनने के लालच में अंग्रेजों का साथ दिया तथा प्लासी के युद्ध (1757) में नवाब से गद्दारी की। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि गांधी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को अपमानित होते देखकर प्रसन्न दिखाई दिए। उन्होंने कहा, ''केवल एक विश्वासघाती ही अपने देश को असफल होते देखकर खुश होता है। कल यह साबित हो गया कि गांधी ही भारत को अपमानित और बदनाम करने के शिल्पकार और डिजाइनर थे।''

अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में 36,607 करोड़ रुपए का बजट पेश, छह प्रमुख क्षेत्रों पर जोर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

ईटानगर/भाषा। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चोवना मेन ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 202627 के लिए 36,607 करोड़ रुपए का बजट पेश किया।

बजट में छह प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया गया है, जिनका उद्देश्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, जन-केंद्रित विकास, आर्थिक वृद्धि और प्रशासनिक सुधार सुनिश्चित करना है। उप मुख्यमंत्री और वित्त, योजना एवं निवेश विभाग के मंत्री चोवना मेन ने बताया कि कुल बजट अनुमान में 701.43 करोड़ रुपए का घाटा है। पिछले वित्त वर्ष में राज्य का बजट 39,842 करोड़ रुपए था जिससे वित्त वर्ष 202627 का यह बजट लगभग 8.1 प्रतिशत कम है।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि इस बजट को छह प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित किया गया है। इसमें बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2,038 करोड़ रुपए और जन-केंद्रित विकास के लिए 3,320 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

अन्य प्राथमिक क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने के लिए 630 करोड़ रुपए, उद्यमिता और रोजगार सृजन के लिए 307 करोड़ रुपए, संसाधन जुटाने और वित्तीय स्थिरता के लिए 188 करोड़ रुपए और शासन सुधार और प्रशासनिक सुधारों के लिए 727 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।

असम में 'अरुणोदय' योजना के तहत 40 लाख महिलाओं को मिली नौ-नौ हजार रुपए की वित्तीय सहायता

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

गुवाहाटी/भाषा। असम में मंगलवार को राज्य सरकार की प्रमुख'अरुणोदय' योजना के तहत 40 लाख परिवारों को 9,000-9,000 रुपए की राशि प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि इन परिवारों की महिलाओं के बैंक खातों में यह राशि भेजना सरकार के संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण का प्रतीक है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यह योजना आगामी विधानसभा चुनावों से संबंधित नहीं है, और साथ ही यह भी बताया कि यह योजना सभी के लिए नहीं है, बल्कि केवल उन महिलाओं के लिए है, जो विशिष्ट मानदंडों को पूरा करती हैं।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, असम में महिला-नेतृत्व वाले परिवारों को सशक्त बनाने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम है। माननीय मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से अरुणोदय योजना के लाभार्थी 40 लाख परिवारों को 9,000 रुपए प्रति परिवार हस्तांतरित किए, इससे राज्य भर में महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा तथा सम्मान को और मजबूती मिली। सीएमओ के अनुसार, राज्य के विभिन्न हिस्सों की लाभार्थी महिलाएं 3,800 से अधिक सार्वजनिक कार्यक्रमों के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये इस केंद्रीय कार्यक्रम से जुड़ीं। ये कार्यक्रम ग्राम पंचायतों, स्वायत्त परिषद क्षेत्रों, ग्राम विकास समितियों और शहरी वार्ड समितियों में आयोजित किए गए थे।

मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी : वैष्णव

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को बताया कि मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, जिसके लिए लगभग 8.7 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। इस परियोजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2019 में की थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के सभी घरों में नल के माध्यम से साफ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है।

वैष्णव ने प्रेसवार्ता में कहा, ''मंत्रिमंडल ने जल शक्ति मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यान्वयन को बुनियादी ढांचे के निर्माण से सेवा वितरण की ओर पुनर्गठित और पुनर्निर्देशित करने की बात कही गई है।'' संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए मंत्रिमंडल ने कुल परिव्यय को बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपए करने की मंजूरी दी है, जिसमें 2019-20 में स्वीकृत 2.08 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 3.59 लाख करोड़ रुपए की कुल केंद्रीय सहायता शामिल है। मंत्री ने कहा कि 'सुजलाम भारत' नामक एक समान राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा स्थापित किया जाएगा, जिसके तहत प्रत्येक गांव को एक अद्वितीय सुजल गांव या सेवा क्षेत्र आईडी आवंटित की जाएगी, जो स्रोत से नल तक संपूर्ण पेयजल आपूर्ति प्रणाली का डिजिटल मानचित्रण करेगी।

यदि सरकारी योजनाओं का सुदृढ़ कार्यान्वयन होता तो गांवों की हालत बदल चुकी होती: कांग्रेस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। सरकार पर वास्तविक आंकड़े बताने की जगह लोकलुभावन तस्वीर दिखाने का आरोप लगाते हुए राज्यसभा में मंगलवार को कांग्रेस ने कहा कि यदि सरकारी योजनाओं का सुदृढ़ कार्यान्वयन होता तो गांवों की हालत बदल चुकी होती।

उच्च सदन में ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस की रजनी अशोकराव पाटिल ने कहा कि गांवों को सशक्त करने से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी लेकिन कागजों पर आंकड़े अलग हैं और वास्तविक स्थिति अलग है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के बजट में केवल चार फीसदी की वृद्धि की गई और 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' की बात करने वाली सरकार खुद यह सोचे कि क्या यह वृद्धि पर्याप्त है। पाटिल ने कहा कि सरकार ऐतिहासिक कदम उठाने का दावा करती है लेकिन यह नहीं देखती कि उसके कथित ऐतिहासिक कदमों से लाभान्वित कितने लोग हुए। ''यदि सरकारी योजनाओं का सुदृढ़ कार्यान्वयन होता तो गांवों की हालत बदल चुकी होती।'' कांग्रेस सदस्य ने कहा कि पिछले कई वर्षों में कई अहम योजनाओं के बजट में कमी आई है तो कई योजनाओं के लिए आवंटित बजट ही पूरी तरह खर्च नहीं हो पाया। गरीबों की मददगार सबसे बड़ी योजना मनरेगा है जो मांग आधारित रोजगार योजना है और सरकार ने इसका नाम बदल दिया। पाटिल ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का नाम बदल कर इसे सरकार ने वीबी जी राम जी योजना कर दिया।

प्रियंका को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया होता तो प्रदर्शन अच्छा होता: रीजीजू का राहुल पर तंज

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर ''गंभीरता पूर्ण व्यवहार नहीं करने'' का मंगलवार को आरोप लगाया और तंज कसते हुए कहा कि यदि प्रियंका गांधी को विपक्ष का नेता बनाया गया होता, तो 'परफॉरमेंस' शायद थोड़ा अच्छा होता।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए सदन में लाये गए संकल्प पर चर्चा में भाग लेते हुए रीजीजू ने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष सदन में जिस तरह का हल्का व्यवहार करते हैं, वैसा ही अपने सांसदों को भी करने के लिए मजबूर करते हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने तंज कसते हुए कहा, ''आपके यहां भी अच्छे लोग हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष उन्हीं (राहुल) को बनाया। हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूं। मेरे हाथ में तो है नहीं।'' उन्होंने सदन में उपस्थित वायनाड सांसद की ओर इशारा करते हुए कहा, ''देखिये प्रियंका गांधी वाद्रा भी पीछे बैठकर मुस्कुरा रही हैं।'' उनकी इस बात पर विपक्षी सदस्यों के बीच भी हल्की-फुल्की चर्चा होते देखी गई।

रीजीजू ने कहा, ''अगर इन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाते, तो भी 'परफॉरमेंस' शायद थोड़ा अच्छा होता। वह कम से कम (सदन में) बैठती तो हैं, सुनती (तो) हैं कम से कम।'' इस पर सदन मे ठहाके गूंज उठे। उन्होंने राहुल गांधी का संदर्भ देते हुए कहा कि ''इनके नेता प्रतिपक्ष तो सुनते ही नहीं।'' इस बीच, प्रियंका अपने स्थान पर खड़ी हो गईं और मंत्री की बात सुनकर मुस्कुराती नजर आईं। फिर, रीजीजू ने कहा, ''मैंने संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते कहा है। किसी भी सांसद का व्यवहार यदि अच्छा है तो मुझे उनकी सराहना करनी चाहिए। मैं भाजपा का सदस्य हूं। लेकिन यदि कोई सांसद अच्छा व्यवहार करता है तो संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते उनकी सराहना करना मेरा दायित्व है।'' रीजीजू का भाषण समाप्त होने के बाद पीठासीन सभापति कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी से कहा, ''आपका नाम लिया गया और आपकी तारीफ (रीजीजू द्वारा) की जा रही थी, आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं।''

राहुल गैरजिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष, उनके खिलाफ अविश्वास का संकल्प लाना चाहिए : ललन सिंह

नई दिल्ली/भाषा। जनता दल (यूनाइटेड) के नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर ''गैरजिम्मेदार'' होने का आरोप लगाया और कहा कि सदन में अध्यक्ष ओम बिरला नहीं, बल्कि राहुल गांधी के खिलाफ अविश्वास का संकल्प लाया जाना चाहिए।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए विपक्ष द्वारा लगाए गए संकल्प पर चर्चा में भाग लेते हुए सिंह ने कहा कि कांग्रेस द्वारा अपने एक नेता की तुष्टीकरण के लिए यह संकल्प लाया गया है। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष के सदस्य दिल पर हाथ रखकर सोचेंगे तो वो इस संकल्प के विरोध में हैं।

सिंह ने आरोप लगाया कि यह संकल्प उच्च सदन के आसन को दबाव में रखने का प्रयास है।

उनका कहना था कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जरूरत पड़ने पर सिर्फ विपक्ष नहीं, बल्कि सत्तापक्ष के लोगों को भी रोकते-टोकते हैं।

शाहजहांपुर में लंबे समय से गैर हाजिर एक उपनिरीक्षक समेत 17 पुलिसकर्मी निलंबित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

शाहजहांपुर (उप्र)/भाषा। शाहजहांपुर जिले में लंबे समय से बिना छुट्टी लिए गैर हाजिर एक उपनिरीक्षक समेत 17 पुलिस कर्मियों को पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजेश द्विवेदी ने मंगलवार को 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि उन्होंने जिले के विभिन्न थानों में 2023 से अनुपस्थित एक उप निरीक्षक तथा पिछले एक वर्ष से अनुपस्थित 16 पुलिस कर्मियों को मंगलवार को निलंबित कर दिया है।

एसपी ने बताया कि उन्होंने जिले में तैनात ऐसे पुलिसकर्मियों की सूची बनाने को कहा था जो लंबे समय से अनुपस्थित हैं और उन्होंने इस दौरान ना तो छुट्टी ली और न ही अनुपस्थित होने का कोई कारण बताया है।द्विवेदी ने कहा कि ऐसे 17 पुलिसकर्मियों के बारे में पता चला जिन्होंने पुलिस विभाग में रहकर अनुशासनहीनता की है, इसलिए उन्हें निलंबित कर दिया गया है।

किसी भी पात्र मतदाता का नाम नहीं हटाया जाएगा, बंगाल चुनाव स्वतंत्र और शांतिपूर्ण होंगे : सीईसी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा और उसकी प्राथमिकता राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करना है।

तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल के बीच आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया है। राज्य में चुनाव तैयारियों पर दो दिन तक राजनीतिक दलों, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कई बैठकें करने के बाद कोलकाता में संवाददाता सम्मेलन में कुमार ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता का हमेशा से ''शांतिपूर्ण और भागीदारी वाले लोकतंत्र'' में विश्वास रहा है। उन्होंने कहा, ''हमारा लक्ष्य बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तथा शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करना है।'' सीईसी ने कहा, ''किसी भी पात्र मतदाता का नाम नहीं हटाया जाएगा।'' मतदाताओं की सूची को लेकर जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर कुमार ने कहा कि यह प्रक्रिया संवैधानिक मानदंडों

के अनुसार पूरे देश में चलाई जा रही है। एसआईआर राजनीतिक रूप से संवेदनशील प्रक्रिया है और इसके कारण तृणमूल कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी आमने-सामने हैं। उन्होंने कहा, ''पूरे भारत में एसआईआर का संचालन संवैधानिक मानदंडों के अनुसार किया जा रहा है।'' सीईसी के अनुसार, मतदाता सूची के पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची ''त्रुटिरहित'' बनी रहे। कुमार ने कहा, ''इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो लोग मतदान करने के पात्र हैं, उनके नाम मतदाता सूची में शामिल हों, जबकि अपात्र लोगों के नाम सूची में नहीं रहें।''

सीईसी ने इस दावे का खंडन किया कि तार्किक विसंगतियां केवल बंगाल के लिए ही सामने लाई गई हैं। उन्होंने कहा, ''पश्चिम बंगाल की तरह ही सभी 12 राज्यों में इस तरह की विसंगतियां उजागर हुई हैं।'' विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान सामने आए आंकड़ों के पैटर्न को समझाते हुए कुमार ने कहा कि जनगणना प्रपत्र जमा करने के बाद लगभग चार-पांच प्रतिशत मतदाता 2002 की मतदाता सूची से अपना मिलान नहीं कर पाए। उन्होंने बताया कि इन्हें 'अमान्य मतदाता' की श्रेणी में रखा गया। कुमार ने कहा, ''जानबूझकर या अनजाने में हुई गलतियों के कारण लगभग सात-आठ प्रतिशत मतदाताओं ने अपना मिलान गलत तरीके से किया था।'' उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कई मामले फिलहाल जांच के लिए लंबित हैं। सीईसी ने कहा, ''पश्चिम बंगाल में ईआरओ और एईआरओ स्तर पर कई मामले अनिर्णीत हैं।''

सोशल मीडिया कंपनियों को अधिक जवाबदेह बनाया जाए: राज्यसभा में मिलिंद देवरा ने की मांग

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। राज्यसभा में शिवसेना के सदस्य मिलिंद मुरली देवरा ने सरकार से सोशल मीडिया कंपनियों को अधिक जवाबदेह बनाने की मांग करते हुए कहा कि डिजिटल मंचों का किशोरों पर नकारात्मक प्रभाव बढ़ता जा रहा है।

राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए देवरा ने बच्चों और किशोरों पर सोशल मीडिया तथा इंटरनेट के उपयोग के प्रभाव को लेकर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने गाजियाबाद में हाल

ही में तीन किशोर बहनों की आत्महत्या की घटना का भी उल्लेख किया, जिसे कथित तौर पर ऑनलाइन खेल की लत से जोड़ा जा रहा है।

देवरा ने कहा कि सोशल मीडिया दुनिया भर में अरबों लोगों को जोड़ता है, आवाजों को सामने लाता है और सूचना को अधिक लोकतांत्रिक बनाता है, लेकिन इसका एक स्याह पक्ष भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि 2010 के आसपास, जब एक प्रमुख सोशल मीडिया मंच ने युवाओं को आक्रामक तरीके से लक्षित करना शुरू किया, तब से किशोरों में अवसाद और आत्महत्या के मामलों में तेज वृद्धि देखी गई। देवरा के अनुसार, भारत में करीब 27 प्रतिशत किशोरों में सोशल मीडिया की लत के लक्षण दिखते हैं, जिससे पढ़ाई में गिरावट, चिंता और आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याएं सामने आती हैं। उन्होंने एक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए कहा कि देश के बड़े शहरों में लगभग 33 प्रतिशत बच्चे साइबर उत्पीड़न का सामना करते हैं।

सुविचार

प्रेम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक एहसास है। इसे शब्दों से ज्यादा अपने व्यवहार और समर्पण से व्यक्त किया जाता है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

कैसी हो भारत की शिक्षा व्यवस्था?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की शिक्षा व्यवस्था को अर्थव्यवस्था की वास्तविक जरूरतों से जोड़ने की प्रक्रिया को तेज करने का आह्वान कर करोड़ों विद्यार्थियों के जीवन को सही दिशा देने की कोशिश की है। अगर यह काम पांच दशक पहले हो जाता तो आज देश में इतनी बेरोजगारी नहीं होती। अब लोग इस मुद्दे पर खुलकर बात करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग पूछ चुके हैं- 'हमने स्कूल में रट-रटकर जो पाठ याद किए, मुर्गा बने, डंडे खाए, परीक्षाओं में रातभर जागकर पढ़ाई की, उसका कितना हिस्सा अब जीवन में काम आ रहा है?' क्या उस पढ़ाई को थोड़ा बेहतर बनाते हुए कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता था, जिससे वह जीवन में काम आती और लोगों को आत्मनिर्भर भी बनाती? आज का विद्यार्थी उस समय ठगा हुआ महसूस करता है, जब उसे पता चलता है कि स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाएं पास करने के लिए कोचिंग करनी होगी। कई प्रतियोगी परीक्षाओं का पाठ्यक्रम ऐसा है, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा उस नौकरी के लिए चुने गए अभ्यर्थियों के जीवन में कोई काम नहीं आता। देश में जैसी शिक्षा व्यवस्था चली आ रही है, उसने युवाओं को कोई कौशल नहीं सिखाया, बल्कि बेरोजगारों की भीड़ पैदा की। आज स्थिति यह है कि उच्च शिक्षा प्राप्त लाखों युवाओं को पता ही नहीं कि उनमें क्या खूबी है और वे जीवन में क्या करना चाहते हैं! कुछ युवा यह आरोप लगाते हैं कि पिछली सरकारों ने जानबूझकर ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू की, जिससे विद्यार्थी दु:खी एवं त्रस्त रहे। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, यह बहस का विषय हो सकता है।

भारत में शिक्षा कैसी होनी चाहिए? इसका जवाब देना बहुत मुश्किल नहीं है। भारत में ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, जो विद्यार्थी को अच्छा इन्सान बनाए। उसे समझदार और जिम्मेदार नागरिक बनाए। उसे सभी देशवासियों के साथ मिलकर रहना सिखाए। वह उसकी जिज्ञासा का दमन न करे, बल्कि सोचना और सवाल करना सिखाए। साथ ही, उसकी रुचि को पहचानकर कम-से-कम कोई एक कौशल जरूर सिखाए, जिससे उसे भविष्य में रोजगार मिले। वर्तमान में लाखों युवा ऐसे हैं, जो बेरोजगारी के कारण परिवार, पड़ोसियों और रिश्तेदारों से ताने सुन रहे हैं। उनकी पीड़ा कौन समझेगा? नेता तो चुनावी मौसम में सरकारी नौकरियां देने की घोषणा कर देते हैं। सरकारी नौकरियां हैं ही कितनी? जिन्हें मिलती भी हैं, उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ता है? क्या इस तरह बेरोजगारी दूर कर पाएंगे? बेरोजगारी का एक ही समाधान है- युवाओं को कौशल सिखाएं। उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। इसकी शुरुआत स्कूल से ही हो। पाठ्यक्रम से उस सामग्री को कम करें या हटाएं, जिसकी जीवन में कम उपयोगिता है या कोई उपयोगिता नहीं है। उसके बारे में सामान्य जानकारी देना काफी रहेगा। रटने और ज्यादा नंबर लाने पर नहीं, बल्कि संभावनाओं और समाधान पर जोर दें। स्कूली पाठ्यक्रम की भाषा शैली में बहुत सुधार की जरूरत है। कुछ सुधार हुआ भी है, लेकिन काफी गुंजाइश है। उसमें रोचकता का समावेश होना चाहिए। किताब ऐसी न हो, जिसकी चार पंक्तियां पढ़ते ही कोई विद्यार्थी सोचे- 'यह तो मेरे लिए नहीं लिखी गई है!' हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए वहां रोजगार की संभावनाएं ढूंढ़ने पर खास जोर दिया जाए। राजस्थान में ऐसे लाखों व्यक्ति हैं, जिन्होंने स्कूल में भूगोल की किताब में समुद्र की गर्म एवं ठंडी जलधाराओं के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन उन्हें अपने गांव के मौसम के बारे में कुछ नहीं बताया गया। वे अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी आदि के उद्योगों के बारे में जानते हैं। उन्हें अपने गांव में उद्योगों से जुड़ीं संभावनाओं के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया गया। शिक्षा व्यवस्था में सुधार समय की मांग है। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तुरंत लागू करना चाहिए।

ट्वीटर टॉक

नई दिल्ली में आयोजित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर महिला सम्मान 2026 कार्यक्रम में नारी शक्ति का अभिनंदन करने का अवसर प्राप्त हुआ। समाजसेवा, शिक्षा, कला और उद्यमिता आदि क्षेत्रों में योगदान देकर ये बहनें आज स्वयं की एक मजबूत पहचान रखती हैं।

-गजेन्द्र सिंह शेखावत

जनसेवा के प्रति आपका समर्पण, लोगों के प्रति आपका स्नेह और समाज के कल्याण के लिए किया गया आपका निरंतर कार्य सदैव प्रेरणादायी रहेगा। आपकी सरलता, आपका व्यक्तित्व और जनहित के लिए आपका योगदान हमारी स्मृतियों और परंपराओं में सदैव जीवित रहेगा।

-वसुंधरा राजे

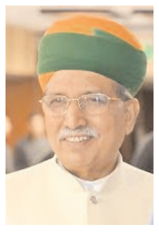

आज भारत सरकार में भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री श्री एच. डी. कुमारस्वामी जी के दिल्ली स्थित निवास पर शिष्टाचार भेंट हुई। इस दौरान विभिन्न समसामयिक राजनीतिक एवं सामाजिक विषयों पर विस्तृत और सार्थक संवाद हुआ।

-अर्जुनराम मेघवाल

प्रेरक प्रसंग

सफलता का रहस्य

अमेरिका के विश्व विख्यात उद्योगपति मिस्टर कारनेगी के पास एक जापानी इंजीनियर आया। वह कारनेगी के कारखाने का अवलोकन करने के बाद बहुत प्रभावित हुआ। भोजन के समय उसने मिस्टर कारनेगी से पूछा, 'आपने इतना बड़ा औद्योगिक साम्राज्य स्थापित किया। इस सफलता का रहस्य क्या है?' उद्योगपति ने कहा, 'सही समय पर सही निर्णय लेना।' उसने दूसरा प्रश्न किया, 'सर, आप सही निर्णय कैसे ले पाते हैं?' उसे उत्तर मिला, 'अनुभवों के आधार पर।' अब इंजीनियर ने तीसरा प्रश्न किया, 'आपने अनुभव प्राप्त कैसे किए?' मिस्टर कारनेगी ने इंजीनियर के कंधे पर हाथ रखा तथा बोले, 'बेटा गलत निर्णयों के दुष्परिणामों से अनुभव होते हैं। उन गलतियों को दोहराएं नहीं। यही संकल्प अनुभव को आगे बढ़ाता है तथा अनुभव व कठोर परिश्रम ही सफलता के शिखर पर पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है।' जापानी इंजीनियर चंद शब्दों में संसार के शीर्षस्थ उद्योगपति की सफलता का रहस्य समझ गया था।

सामयिक

वैश्विक युद्धोन्माद के बीच विश्व शांति की पुकार

ललित गर्ग
मोबाइल : 9811051133

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विश्व ने एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की थी जिसमें शक्ति को नियमों और संस्थाओं के माध्यम से नियंत्रित किया जा सके। लगभग आठ दशकों तक यह वैश्विक व्यवस्था अनेक उतार-चढ़ावों के बावजूद किसी-न-किसी रूप में कायम रही। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, बहुपक्षीय समझौते, कूटनीतिक संवाद और साझा नियम-इन सबका उद्देश्य यही था कि दुनिया 'मत्स्य-न्याय' यानी शक्तिशाली द्वारा कमजोर को निगल जाने की प्रवृत्ति से बची रहे। इसी सोच के तहत युनाइटेट नेशनस, वर्ल्ड ट्रेड ऑरगेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑरगेनाइजेशन, यूनेस्को और अनेक अंतरराष्ट्रीय मंचों की स्थापना हुई। इन संस्थाओं ने विश्व राजनीति को पूरी तरह आदर्श नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने कम-से-कम इतना अवश्य सुनिश्चित किया कि शक्ति के साथ नियम और नैतिकता का एक आवरण बना रहे। परंतु आज यह व्यवस्था अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रही है।

विश्व राजनीति में एक नया रुझान तेजी से उभर रहा है जिसमें सहयोग, संवाद और बहुपक्षीयता की जगह एकपक्षीय कार्रवाई, सैन्य शक्ति और त्वरित लाभ की मानसिकता को प्राथमिकता दी जा रही है। विशेष रूप से डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व में अमेरिका की नीतियों ने इस प्रवृत्ति को और तेज कर दिया है। जो देश कभी वैश्विक नियम-आधारित व्यवस्था का प्रमुख निर्माता और संरक्षक था, वही अब अनेक अंतरराष्ट्रीय समझौतों और संस्थाओं से दूरी बनाता दिखाई देता है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में ही यह संकेत मिल गया था जब अमेरिका ने पेरिस क्लाइमेंट अग्रीमेंटस, इरान न्यूक्लियर डील्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनेस्को जैसी संस्थाओं से खुद को अलग करने की प्रक्रिया शुरू की। इन कदमों का संदेश यह था कि यदि किसी समझौते से तात्कालिक राष्ट्रीय हित प्रभावित होते हैं तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। इससे वैश्विक सहयोग की उस भावना को गहरा आघात पहुंचा, जो दशकों से अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की आधारशिला रही है।

आज स्थिति और भी जटिल हो गई है। दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध और संघर्ष सामान्य घटनाओं की तरह स्वीकार किए जाने लगे हैं। चार वर्षों से जारी रूस-यूक्रेन युद्ध और दो वर्षों से चल रहा गाजा युद्ध इसका सबसे दुखद एवं विडम्बनापूर्ण उदाहरण हैं। इन संघर्षों ने लाखों लोगों के जीवन को संकट में डाल दिया है, शहरों को खंडहर में बदल दिया है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को अस्थिर बना दिया है। युद्ध की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वह किसी स्थायी समाधान की ओर नहीं ले जाता। युद्ध में विजय का दावा करने वाले भी अंततः विनाश और पीड़ा के साथ ही जीते हैं। इतिहास गवाह है कि युद्ध ने कभी भी मानवता को गौरव नहीं दिया; उसने केवल तबाही, भय और अस्थिरता को जन्म दिया है। युद्ध के परिणामस्वरूप पर्यावरण का भारी नुकसान होता है, आर्थिक संसाधन नष्ट हो जाते हैं, महंगाई बढ़ती है, रोजगार के अवसर घटते हैं और समाज में असुरक्षा तथा अविश्वास की भावना गहरी हो जाती है।

आज विश्व के सामने सबसे बड़ी चिंता यह है कि युद्ध और हिंसा धीरे-धीरे सामान्यीकृत होते जा रहे हैं। अनेक बार युद्ध का उद्देश्य वास्तविक समाधान नहीं बल्कि घरेलू राजनीति में छवि निर्माण, शक्ति प्रदर्शन या आंतरिक संकटों से ध्यान हटाना बन जाता है। ऐसी परिस्थितियों में वैश्विक नैतिकता और अंतरराष्ट्रीय कानून दोनों कमजोर पड़ते हैं। यदि शक्तिशाली देश ही नियमों को तोड़ने लगें तो पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाती है। मानवाधिकारों के प्रश्न पर भी दोहरे मानदंड दिखाई देते हैं। किसी एक देश की आलोचना की जाती है, लेकिन उसी तरह के कृत्यों पर दूसरे देशों के संदर्भ में चुप्पी साध ली जाती है। इससे मानवाधिकार एक सार्वभौमिक मूल्य के बजाय भू-राजनीतिक बहस का उपकरण बन जाते हैं। यदि विश्व समुदाय वास्तव में मानवता की रक्षा करना चाहता है तो उसे हर देश के लिए समान मानदंड अपनाने होंगे। इन परिस्थितियों में यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या दुनिया फिर से उस दौर की ओर बढ़ रही है जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति का नियम बन जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो यह केवल छोटे देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए गंभीर खतरा होगा।

यदि विश्व समुदाय मिलकर युद्ध के स्थान पर संवाद और सहयोग को अपनाए तो न केवल वैश्विक स्थिरता कायम होगी बल्कि मानवता विकास और समृद्धि के नए मानक भी स्थापित कर सकेगी। यही आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है और यही भविष्य की सबसे बड़ी आशा भी। आज जब विश्व युद्ध, हिंसा और शक्ति-प्रतिस्पर्धा के तनाव से जूझ रहा है, तब दुनिया की निगाहें स्वाभाविक रूप से भारत की ओर उठती हैं। भारत वह धरती है जहाँ शांति, सह-अस्तित्व और अहिंसा केवल राजनीतिक नीतियाँ नहीं बल्कि जीवन-दर्शन के रूप में विकसित हुए हैं।

भारत का ऐतिहासिक दृष्टिकोण इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता के बाद से भारत ने संप्रभुता, गैर-हस्तक्षेप और बहुपक्षीय सहयोग की नीति का समर्थन किया है। भारत का यह विश्वास रहा है कि वैश्विक समस्याओं का समाधान केवल सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। यही कारण है कि भारत ने हमेशा शांति, संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता दी है। आज जब विश्व व्यवस्था डगमगा रही है, तब भारत की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत न केवल एक उभरती आर्थिक शक्ति है बल्कि एक ऐसी सभ्यता का प्रतिनिधि भी है जिसने सदियों से अहिंसा, सह-अस्तित्व और मानवता के मूल्यों को महत्व दिया है। महात्मा गांधी की अहिंसा की परंपरा और भारत की आध्यात्मिक विरासत आज भी विश्व को दिशा दे सकती है।

यदि विश्व समुदाय मिलकर युद्ध के स्थान पर संवाद और सहयोग को अपनाए तो न केवल वैश्विक स्थिरता कायम होगी बल्कि मानवता विकास और समृद्धि के नए मानक भी स्थापित कर सकेगी। यही आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है और यही भविष्य की सबसे बड़ी आशा भी। आज जब विश्व युद्ध, हिंसा और शक्ति-प्रतिस्पर्धा के तनाव से जूझ रहा है, तब दुनिया की निगाहें स्वाभाविक रूप से भारत की ओर उठती हैं। भारत वह धरती है जहाँ शांति, सह-अस्तित्व और अहिंसा केवल राजनीतिक नीतियाँ नहीं बल्कि जीवन-दर्शन के रूप में विकसित हुए हैं। इसी भूमि से वसुधैव कुटुम्बकम का वह महान मंत्र निकला जिसने संपूर्ण मानवता को एक परिवार के रूप में देखने की दृष्टि दी। महात्मा गांधी ने इसी भारतीय परंपरा को आधुनिक युग में अहिंसा की शक्तिशाली राजनीतिक और नैतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया और दुनिया को बताया कि संघर्षों का समाधान हिंसा से नहीं बल्कि सत्य, करुणा और संवाद से संभव है। भारत की आध्यात्मिक विरासत-जिसमें महावीर और गौतम बुद्ध जैसे महापुरुषों की शिक्षाएँ समाहित हैं, मानवता को यह संदेश देती है कि शांति ही स्थायी विकास और वैश्विक संतुलन का आधार है। आज की अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों में भारत की यही अहिंसात्मक दृष्टि, उसकी आध्यात्मिक शक्ति और सर्वहित की भावना विश्व को एक नई दिशा दे सकती है तथा मानवता को संघर्ष की अंधी दौड़ से निकालकर सहयोग, सद्भाव और स्थायी शांति के मार्ग पर अग्रसर कर सकती है।

नजरिया

आज जरूरत इस बात की है कि हम स्वयं भी धूम्रपान से दूर रहें और दूसरों को भी इसके खतरों के बारे में जागरूक करें। आखिरकार, एक स्वस्थ समाज की शुरुआत स्वस्थ व्यक्तियों से ही होती है। यदि हम तंबाकू से दूरी बनाकर जीवन को अपनाएं तो न केवल अपना स्वास्थ्य सुरक्षित रख सकते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर और सुरक्षित वातावरण तैयार कर सकते हैं।

धूम्रपान-मुक्त पीढ़ी ही है स्वस्थ भविष्य की बुनियाद

योगेश कुमार गोयल
मोबाइल : 9416740584

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है लेकिन दुर्भाग्य से धूम्रपान और तंबाकू की लत इस अमूल्य धन को तेजी से नष्ट कर रही है। हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को 'नो स्मोकिंग डे' मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को धूम्रपान की आदत छोड़ने के लिए प्रेरित करना और समाज को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है। इस वर्ष यह दिवस 11 मार्च को मनाया जा रहा है। यह एक ऐसा अवसर है, जब लोग अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकते हैं और धूम्रपान मुक्त जीवन की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। हर वर्ष इस दिन एक विशेष थीम के साथ लोगों को तंबाकू से दूर रहने का संदेश दिया जाता है। इस वर्ष का संदेश है धूम्रपान से मुक्त जीवन की शुरुआत एक धूम्रपान-मुक्त दिन से होती है।' इसका अर्थ स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति केवल एक दिन भी धूम्रपान से दूरी बना ले तो वह आगे चलकर इसे पूरी तरह छोड़ने की दिशा में पहला कदम उठा सकता है।

तंबाकू और निकोटीन की लत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार तंबाकू के कारण हर वर्ष लगभग 80 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। इनमें से करीब 70 लाख लोग सीधे धूम्रपान करने वाले होते हैं जबकि लगभग 12 लाख लोग ऐसे होते है, जो स्वयं धूम्रपान नहीं करते लेकिन दूसरों के धुएं के संपर्क में आने के कारण गंभीर बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। यह स्थिति बताती है कि धूम्रपान केवल करने वाले व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके आसपास रहने वाले परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। हाल के वर्षों में देखा गया है कि दुनिया के कई देशों में धूम्रपान करने वालों की संख्या में कमी आई है लेकिन इसके बावजूद चिंता का विषय यह है कि युवाओं और किशोरों में तंबाकू के उपयोग की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है।

वैश्विक रिपोर्टों के अनुसार 13 से 15 वर्ष की आयु के लगभग 3.7 करोड़ बच्चे किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। ई-सिगरेट और अन्य नए निकोटीन उत्पादों ने इस समस्या को और जटिल बना दिया है। आकर्षक पैकेजिंग, फ्लेवर और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए इन उत्पादों को युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाने की कोशिश की जा रही है। विज्ञापन प्रतिबंधों के बावजूद सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से युवाओं को लक्ष्य बनाकर प्रचार किया जाता है। इस कारण किशोरों में तंबाकू की लत तेजी से फैल रही है, जो भविष्य में गंभीर स्वास्थ्य संकट का रूप ले सकती है।

तंबाकू के दुष्प्रभाव केवल कैंसर तक सीमित नहीं हैं। यह शरीर के लगभग हर अंग को नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान फेफड़ों के कैंसर का प्रमुख कारण है और दुनिया में होने वाली फेफड़ों के कैंसर से लगभग 85 प्रतिशत मौतें धूम्रपान के कारण होती हैं। इसके अलावा तंबाकू हृदय रोग, स्ट्रोक, दमा, ब्रोंकाइटिस और कई अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों को जन्म देता है। लंबे समय तक तंबाकू का सेवन करने से मुंह, गले, पेट, लीवर और आंतों के कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है।

तंबाकू की समस्या भारत में भी काफी गंभीर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के 25 करोड़ से अधिक लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। इनमें अधिकांश पुरुष हैं लेकिन महिलाओं में भी इसका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। भारत में तंबाकू सेवन के कई रूप प्रचलित हैं, जैसे खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा और सुपारी के साथ तंबाकू का सेवन। इन उत्पादों की आसान उपलब्धता और कम कीमत के कारण लोग जल्दी इसकी लत के शिकार हो जाते हैं।

धूम्रपान केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक और सामाजिक समस्याओं को भी जन्म देता है। तंबाकू की लत व्यक्ति को धीरे-धीरे निर्भर बना देती है। कई युवाओं में यह लत अवसाद, चिंता और आत्मविश्वास की कमी जैसी मानसिक समस्याओं को भी जन्म देती है। जब किशोरावस्था में यह आदत लग जाती है तो उसे छोड़ना बेहद कठिन हो जाता है और इसका प्रभाव उनके पूरे जीवन पर पड़ता है। धूम्रपान के खतरों को देखते हुए समाज में व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है। सरकारों ने तंबाकू नियंत्रण के लिए कई कानून बनाए हैं, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया है और तंबाकू उत्पादों पर चेतावनी संदेश भी अनिवार्य किए हैं। इसके बावजूद केवल कानून से इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। इसके लिए सामाजिक जागरूकता और व्यक्तिगत संकल्प दोनों जरूरी हैं। पत्रकारिता के अपने लंबे अनुभव के दौरान मैंने नशे के दुष्प्रभावों पर व्यापक अध्ययन किया है। वर्ष 1993 में मेरी पुस्तक मौत को खुला निमंत्रण' प्रकाशित हुई थी, जिसमें तंबाकू और अन्य नशों से होने वाले भयानक परिणामों का विस्तार से उल्लेख किया गया था। उस समय भी यह चेतावनी दी गई थी कि यदि समाज ने समय रहते नशे के खिलाफ जागरूकता नहीं बढ़ाई तो इसके दुष्परिणाम आने वाली पीढ़ियों को भुगतने पड़ेंगे। आज तीन दशक बाद भी यह चिंता उतनी ही प्रासंगिक दिखाई देती है।

बहरहाल, नो स्मोकिंग डे हमें याद दिलाता है कि जीवन का हर पल अमूल्य है और इसे किसी भी तरह की लत के कारण बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। धूम्रपान छोड़ना कठिन अवश्य है लेकिन असंभव नहीं। यदि व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर ले और परिवार तथा समाज का सहयोग मिले तो वह आसानी से इस लत से मुक्त हो सकता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम स्वयं भी धूम्रपान से दूर रहें और दूसरों को भी इसके खतरों के बारे में जागरूक करें। आखिरकार, एक स्वस्थ समाज की शुरुआत स्वस्थ व्यक्तियों से ही होती है। यदि हम तंबाकू से दूरी बनाकर जीवन को अपनाएं तो न केवल अपना स्वास्थ्य सुरक्षित रख सकते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर और सुरक्षित वातावरण तैयार कर सकते हैं। इसलिए इस नो स्मोकिंग डे पर संकल्प लें कि तंबाकू का साथ छोड़कर हर सांस को कीमती बनाएंगे और जीवन को स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे।

महत्त्वपूर्ण

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company,6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**, (*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**RNI No. 58061/93. Regn No.: RNP/KA/BGS/2050/2015-2017 posted at Bengaluru PSO Mysore Road Bengaluru-560 026**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।– दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ईरानी स्कूल पर हमले में अमेरिकी मिसाइल के कथित इस्तेमाल का नया वीडियो आया सामने

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

यरुशलम/एपी। एक नए वीडियो फुटेज से यह आशंका मजबूत हुई है कि अमेरिका ने दक्षिणी ईरान में एक परिसर पर अपनी टॉमहॉक मिसाइल से हमला किया था। यह परिसर उस स्कूल के पास स्थित है, जहां पश्चिम एशिया में जारी युद्ध की शुरुआत में हुए विस्फोट में 165 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।

जांचकर्ताओं का कहना है कि 28 फरवरी को हुआ यह हमला ईरान के मिनाब शहर में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के एक ठिकाने के पास स्थित स्कूल के निकट हुआ था। यह क्षेत्र होरमोजगन प्रांत में आता है।

इस हमले का एक नया वीडियो सामने आया है जिसकी जांच 'बेलिंगकैट' नामक जांच समूह ने की। इस वीडियो में एक मिसाइल को इमारत से टकराते और आसमान में काला धुआं उठते हुए देखा गया है।

समाचार एजेंसी 'एसोसिएटेड प्रेस' ने इस वीडियो की भौगोलिक स्थिति की जांच में पाया कि इसे स्कूल के पास के ही इलाके से रिकॉर्ड किया गया था, जहां पहले से ही धुआं उठ रहा था।

बेलिंगकैट समूह के शोधकर्ता ट्रेवर बॉल ने हमले में इस्तेमाल हथियार की पहचान टॉमहॉक क्रूज मिसाइल के रूप में की है,जो केवल अमेरिका के ही पास मौजूद है। 'यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड' ने इस युद्ध में टॉमहॉक मिसाइलों के इस्तेमाल की पुष्टि की है और 28 फरवरी को यूएसएस स्प्रुएन्स द्वारा मिसाइल दागे जाने की तस्वीर भी जारी की थी। यह जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन विमानवाहक पोत समूह का हिस्सा है, जो हमले के इलाके की मारक दूरी में था।

बेलिंगकैट ने कहा कि यह फुटेज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे का खंडन करता हुआ लग रहा है, जिसमें उन्होंने घातक विस्फोट के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया था।

ट्रंप ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ईरान के पास भी टॉमहॉक क्रूज मिसाइल हो सकती है। यह मिसाइल अमेरिकी रक्षा कंपनी रेथियोन बनाती है और जापान व ऑस्ट्रेलिया जैसे सहयोगी देशों को बेची जाती है। ईरान के पास इसके होने का कोई प्रमाण नहीं है।

ट्रंप ने कहा, यह मिसाइल कई देशों को बेची जाती है और इस्तेमाल की जाती है। ईरान के पास भी कुछ टॉमहॉक हो सकते हैं। इस बीच, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका इस घटना की जांच कर रहा है।

अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि किसी घटना में अमेरिकी सेना की संभावित भूमिका सामने आती है तो उसकी समीक्षा शुरू की जाती है। इसी के तहत इस हमले का भी आकलन किया जा रहा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि स्कूल की लोकेशन भी इस आशंका को बल देती है, क्योंकि वह रिवोल्यूशनरी गार्ड के ठिकाने और नौसैनिक इकाई की बैरक के पास स्थित है। अमेरिका पहले ही इस प्रांत में नौसैनिक लक्ष्यों पर हमले की बात स्वीकार कर चुका है।

श्रीलंका ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आठ प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी की

कोलंबो/भाषा। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से कच्चे तेल में आई तेजी के बीच श्रीलंका ने सोमवार आधी रात से खुदरा ईंधन कीमतों में आठ प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी कर दी है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पेट्रोल एवं डीजल की खुदरा कीमतों में यह बढ़ोतरी ऐसे समय की गई है जब वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें चार साल में पहली बार 100 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गई हैं।

सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी सीलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (सीपीसी) ने कहा कि संशोधित दरों के तहत व्यापक रूप से उपयोग होने वाले पेट्रोल और डीजल के दाम में प्रति लीटर 22 श्रीलंकाई रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कंपनी ने कहा कि यह कदम ईंधन की जमाखोरी और घबराहट में की जा रही खरीद को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।

सीपीसी के एक अधिकारी ने कहा, पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति की खबर आने के बाद से ईंधन की खपत में भारी वृद्धि देखी गई है।

सहायता

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को 'ओरुनोडोई' योजना के तहत वित्तीय सहायता हस्तांतरित की। इस योजना के माध्यम से राज्य के महिला-प्रधान परिवारों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजी गई है।

चीन का निर्यात जनवरी-फरवरी में 22 प्रतिशत बढ़ा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

हांगकांग/एपी। अमेरिका के साथ व्यापार में कमी आने के बावजूद चीन का निर्यात वर्ष 2026 के पहले दो महीनों में सालाना आधार पर लगभग 22 प्रतिशत बढ़ गया।

चीन के सीमा शुल्क प्रशासन की तरफ से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी-फरवरी 2026 की अवधि में चीन का आयात लगभग 20 प्रतिशत बढ़ा, जबकि दिसंबर में यह वृद्धि 5.7 प्रतिशत थी। अमेरिका से चीन के आयात में सालाना आधार पर लगभग 27 प्रतिशत की गिरावट आई। हालांकि इस अवधि में निर्यात में 22 प्रतिशत की वृद्धि अर्थशास्त्रियों के अनुमान से अधिक रही। यह दिसंबर में दर्ज 6.6 प्रतिशत की वृद्धि दर से काफी ज्यादा है।

अमेरिका के साथ तनाव के बावजूद चीन का निर्यात बढ़ना उसकी अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक माना जा रहा है। वर्ष 2025 में चीन का निर्यात 5.5 प्रतिशत बढ़ा और उसका व्यापार अधिशेष बढ़कर लगभग 1.2 लाख करोड़ डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।

हालांकि पिछले दो महीनों में चीन से अमेरिका को होने वाले निर्यात में करीब 20 प्रतिशत की गिरावट आई है। लेकिन इस दौरान यूरोप एवं लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में निर्यात बढ़ा है।

जनवरी-फरवरी अवधि में चीन का वैश्विक व्यापार अधिशेष 213.6 अरब डॉलर रहा। चीन आम तौर पर इन दो महीनों के व्यापार आंकड़े एक साथ जारी करता है ताकि चंद्र नववर्ष अवकाश के कारण होने वाले मौसमी प्रभाव को कम किया जा सके। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन पिछले कुछ वर्षों से संपत्ति क्षेत्र में मंदी के कारण दबाव में है। यही कारण है कि चीन ने वर्ष 2026 के लिए आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य 4.5 से 5.0 प्रतिशत तय किया है जो 1991 के बाद सबसे कम है।

उपलब्धि

चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा आयोजित 'उल्लास: नव-साक्षरों का अलंकरण समारोह' में नए साक्षरों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने 99.93 प्रतिशत साक्षरता दर हासिल कर ली है।

जामनगर रिफाइनरी में एलपीजी का उत्पादन अधिकतम किया जाएगा : रिलायंस

नयी दिल्ली/भाषा

उद्योगपति मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मंगलवार को कहा कि उसका विशाल जामनगर तेल रिफाइनरी परिसर रसोई गैस एलपीजी का उत्पादन अधिकतम करेगा, जबकि बंगाल की खाड़ी के केजी-डी6 क्षेत्र से गैस को प्राथमिक क्षेत्र को उपलब्ध कराने के लिए मोड़ा जाएगा, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को पश्चिम एशिया में युद्ध से होने वाले व्यवधानों से उबरने में मदद मिल सके। कंपनी ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब सरकार ने औद्योगिक उपयोगकर्ताओं के लिए एलपीजी आपूर्ति को घरेलू उपभोक्ताओं की ओर मोड़ दिया है, ताकि आम आदमी को पश्चिम एशिया में युद्ध के प्रभाव से सुरक्षित रखा जा सके।

मिडलाइफ कोई संकट नहीं बल्कि महिला की असली ताकत का उदय है : लिसा रे

मुंबई/एजेन्सी

फिल्म 'कसूर' से भारतीय सिनेमा में लोकप्रियता हासिल करने वाली कनाडाई-भारतीय अभिनेत्री लिसा रे अब भले ही स्क्रीन पर दिखाई नहीं देती हैं लेकिन वे सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं के स्वास्थ्य, उम्र बढ़ने और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर खुलकर बात करती रहती हैं। लिसा रे ने मंगलवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने विचार व्यक्त किए। इस पोस्ट में उन्होंने मिडलाइफ के बारे में अपने भाव व्यक्त किए। अभिनेत्री ने लिखा, जब शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने लगता है, तो कई बदलाव आते हैं। लोग अब दूसरों को खुश करने की पुरानी आदत छोड़ देते हैं। खुद पर शक करना कम हो जाता है और मन की शांति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लगती है। वहीं, अपनी बनाई गई सीमाएं और नियम मजबूत होने लगते हैं।

लिसा ने लिखा, मिडलाइफ वह दौर है जब हार्मोन के बदलाव के साथ-साथ जिंदगी की बेकार चीजें भी दूर हो जाती हैं। अब कम माफी मांगते हैं, कम खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं। अपनी कीमत खुद समझ आती है। जरूरत पड़ने पर साफ 'ना' कहना आसान हो जाता है और जीवन ज्यादा सुकून से जीने लगता है।

अपनी बात को खत्म करते हुए अभिनेत्री ने लिखा कि मिडलाइफ कोई संकट या क्राइसिस नहीं है बल्कि यह वह खास समय है जब महिला अपनी असली ताकत के साथ जीना शुरू करती है। यह जीवन की कहानी का दूसरा हिस्सा होता है, जो आखिरकार पूरी तरह उसका अपना होता है। सच तो यह है कि महिलाओं की जिंदगी का यह सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली दौर होता है। लिसा रे 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री और मॉडल हैं। उन्होंने साल 1994 में फिल्म 'हंसते खेलते' से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था, लेकिन असल पहचान उन्हें फिल्म कसूर से मिली थी। इसके बाद वे 'वाटर' और 'आई कांट थिंक स्ट्रेट' जैसी फिल्मों में नजर आई थीं। हालांकि, करियर के पीक पर ही उन्हें कैंसर हो गया था और उन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया था। हालांकि अब वह ठीक हैं और उन्होंने कैंसर से जंग जीत ली है।

आपत्तिजनक पोस्ट मामले में भोजपुरी एक्ट्रेस को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने नेहा सिंह राठौर को दी अग्रिम जमानत

नई दिल्ली/एजेन्सी

सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को अग्रिम जमानत दे दी है है, हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया है कि जांच प्रक्रिया जारी रहेगी और उन्हें जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करना होगा। इस पोस्ट को लेकर लखनऊ में नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

सुनवाई के दौरान जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदूरकर की बेंच ने नेहा सिंह राठौर को अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि कोर्ट के पहले दिए गए निर्देश के अनुसार नेहा सिंह राठौर जांच अधिकारियों के सामने पेश हो चुकी हैं और उनका बयान दर्ज कर लिया गया है।

इसी आधार पर अदालत ने उन्हें राहत देते हुए कहा कि फिलहाल उनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें आगे भी जांच में पूरा सहयोग करना होगा। इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी थी। उस समय अदालत ने निर्देश दिया था कि नेहा सिंह राठौर को जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पहली बार 9 जनवरी को उन्हें जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा और अगर वह ऐसा नहीं करती हैं तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। दरअसल यह पूरा मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई एक पोस्ट से जुड़ा है।

आरोप है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद नेहा सिंह राठौर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ ऐसे बयान लिखे थे, जिन्हें आपत्तिजनक और भड़काऊ माना गया। इसी को आधार बनाकर उनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उनकी पोस्ट से दो समुदायों के बीच नफरत फैल सकती है और इससे सामाजिक माहौल खराब हो सकता है।

एफआईआर में यह भी कहा गया कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हुई थी। इस संवेदनशील घटना के बाद राठौर की ओर से किए गए कथित पोस्ट को लेकर कई लोगों ने आपत्ति जताई थी। शिकायतकर्ताओं का कहना था कि इस तरह के बयान देश की सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव को प्रभावित कर सकते हैं। इसी आधार पर पुलिस ने उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

बॉलीवुड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने मंगलवार को मुंबई में अपने पति जैकी भगनानी के साथ फोटोग्राफरों के लिए पोज दिए।

टीवी के बाद अब ओटीटी पर जादू बिखेरेंगी रूप दुर्गापाल

मुंबई/एजेन्सी

'स्वरागिनी,' 'कुछ रंग प्यार के ऐसे भी,' और 'बालवीर' जैसे कई धारावाहिकों में काम कर घर-घर में अपनी पहचान बना चुकी अभिनेत्री रूप दुर्गापाल अब ओटीटी डेब्यू करने जा रही हैं। दरअसल, अभिनेत्री जल्द ही आगामी वेब सीरीज 'संकल्प' में नजर आएंगी। इस सीरीज में वे अभिनेता मोहम्मद जीशान अय्यूब की पत्नी माधुरी के किरदार में हैं। रूप ने अपने को-स्टार जीशान के अभिनय की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा, जीशान बहुत ही शानदार अभिनेता है। एनएसडी से पढ़ाई करने और फिल्मों-वेब सीरीज में इतना अनुभव होने के कारण उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उनके सीन्स को देखने का नजरिया, भाषा पर अच्छी पकड़ और एनर्जी ने मेरे साथ के सीन को बेहतर बनाया। मैं हर दिन सेट पर उनके आने का इंतजार करती थी। अभिनेत्री ने आगे सीरीज की पूरी टीम की सराहना की। उन्होंने बताया कि शानदार कलाकारों के साथ काम करना ही उन्हें इस प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए उत्साहित कर रहा था। अभिनेत्री ने कहा, जब सबके पास अच्छा काम होता है, तो सेट पर और बाहर भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नाना पाटेकर सर और प्रकाश सर के साथ काम करना एक्टिंग, फिल्म बनाने और जिंदगी के कई पहलुओं को समझने जैसा था। मेघना मलिक से भी बहुत कुछ सीखा। हम लंच और डिनर के दौरान भी खूब बातें करते थे। वे न सिर्फ बेहतरीन एक्टर हैं, बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी हैं।

उन्होंने आगे बताया कि सीरीज के लिए उन्हें ऑफर कैसे मिला था। उन्होंने बताया, साल 2019 तक मैंने टेलीविजन से आगे जाने के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन कोविड के दौरान सब कुछ बदल गया। लोगों को जाते देखकर मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी बहुत छोटी है। कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तब मैंने फैसला लिया कि अब उन चीजों को आजमाना है जिनसे पहले डर लगता था। उत्तराखंड के अल्मोड़ा की रहने वाली अभिनेत्री रूप ने सिल्वर स्क्रीन पर परफॉर्म करने के अलावा, थिएटर में भी काम किया, जो उनके लिए नया था। उन्होंने थिएटर को लेकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया, बिना कट, रीटेक के, महीनों रिहर्सल करके स्टेज पर परफॉर्म करना काफी अजीब था, लेकिन जिंदगी की अनिश्चितता ने मुझे हिम्मत दी। स्टेज पर खड़े होकर बिना किसी डर के परफॉर्म करना शानदार अनुभव था। इसी हिम्मत ने मुझे टीवी से आगे बढ़कर वेब सीरीज में आने की ताकत दी। अभिनेत्री का मानना है कि हर किसी का सफर अलग होता है और सब कुछ अपने सही समय पर ही होता है। उन्होंने कहा, शायद मेरा सफर ऐसा ही होना था। सालों की संख्या मायने नहीं रखती। मैं बहुत खुश हूं कि यह सब अपने आप हुआ। सीरीज का निर्देशन प्रकाश झा ने किया है। रूप ने निर्देशक की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, प्रकाश सर के साथ काम करना किसी बड़े संस्थान में पढ़ाई करने जैसा था। साथ ही काम में मजा भी आता था और यादगार पल भी बनते थे।

इंदौर के संगीत घराने से ताल्लुक रखने वाले शाहबाज ने चुनी अभिनय की राह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

इंदौर। कहते हैं कि भाग्य कहां ले जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। हिंदी सिनेमा में कई ऐसे स्टार्स आए, जो किसी दूसरे प्रोफेशनल से ताल्लुक रखते थे। ऐसे ही सिनेमा और टीवी पर चमकने वाले अभिनेता शाहबाज खान को भी नहीं पता था कि उन्हें करना क्या है लेकिन भाग्य और मेहनत के भरोसे उन्होंने फैंस के दिलों पर राज किया और आज भी टीवी पर अपने निगेटिव किरदारों से राज कर रहे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि अभिनेता के पिता हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गज गायक थे, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत को नया रूप दिया था। 10 मार्च को इंदौर में जन्मे शाहबाज शाही घराने से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गज गायक उस्ताद अमीर खान थे, जिन्होंने आज गावत मन मोरा झूम के, जिन के मन में राम बिराजे और बैरागी रूप धरे जैसे गाने गाए थे। उनके दादा शामीर खान भी सारंगी वादक थे। इतने बड़े घराने से आने के बावजूद भी अभिनेता को संगीत से दूर रखा गया क्योंकि उनकी मां ही नहीं चाहती थी कि वो गायक बनें। दरअसल, अभिनेता की मां नहीं चाहती थी कि भरी महफिल में कोई यह कहे कि उस्ताद अमीर खान का बेटा कैसा गाता है। जब शाहबाज छोटे थे, तभी उनके पिता

का निधन हो गया और उस वक्त उन्हें संगीत की तालीम देने वाला कोई नहीं था। अगर वे किसी और घराने में संगीत सीखने जाते तो कई तरह की बातें होतीं। अभिनेता ने खुद इंटरव्यू में कहा था कि मां ने कहा था कि भले ही रिक्शा चला ले लेकिन संगीत नहीं सीखना है।

अभिनेता की शुरुआती पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल में हुई, जहां उन्होंने अकेले खुद को संभालना सीखा। वह छोटी उम्र में ही समझदार बन चुके थे लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि भाग्य उन्हें सिनेमा की तरफ लेकर जाने वाला है। होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद भी उन्हें नहीं पता था कि करना क्या है लेकिन एक दोस्त के बुलाने पर मुंबई चले गए,जहां उन्होंने कई महीनों तक थिएटर सीखा और उनकी किस्मत तब चमकी, जब उन्हें टीवी सीरीज 'टीपू सुल्तान' में हैदर अली का रोल मिला। पहले टीवी सीरीज कुछ ही एपिसोड में खत्म होने वाली थी लेकिन अभिनेता की किस्मत ने साथ दिया और उन्होंने 58 एपिसोड तक काम किया। टीपू सुल्तान शाहबाज़ को पहचान दिलाने के लिए काफी था। उन्हें उर्दू की बेहतर समझ के चलते सीरियल ऑफर हुआ, जिसके बाद वो 'चंद्रकांता', 'बेताल पचीसी' और 'द ग्रेट मराठा' जैसे सीरियल में दमदार रोल में दिखे। सीरियल में पहचान बनाने के बाद उन्होंने फिल्मों का रूख किया। शुरुआत भले ही फिल्म 'नाचनेवाले गानेवाले' से हुई, लेकिन बाद में कैसे-कैसे रिश्ते, धरतीपुत्र, जिद्दी, युग और मेजर साब जैसी फिल्मों में सिनेमा के खरतनाक विलेन बनकर उभरे। आज भी अभिनेता टीवी और ओटीटी की दुनिया पर राज कर रहे हैं।

गौग्रास

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

बेंगलूरु के चंदापुरा स्थित नंदा नंदी गौशाला में गौ भक्त मंडल देवरबिशनहल्ली के सदस्यों द्वारा गायों के गौ ग्रास हेतु एक ट्रक हरा चारा भेंट किया तथा अपने हाथों से गायों को चारा खिलाया। ज्ञातव्य है कि यह गौभक्त मंडल हर माह गायों हेतु करीब 3-4 ट्रक हरा चारा उपलब्ध कराता है। इस अवसर पर सुरेश पटेल, प्रहलादसिंह राजपुरोहित, मुकनसिंह, हरीश राजपुरोहित, किशोर प्रजापत, राजू सीरवी, प्रकाश प्रजापत, जीतू पटेल सहित गौ भक्त मंडल के अनेक सदस्य उपस्थित थे।

करााबी निगम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। यहां के बिन्नीपेट स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम क्षेत्रीय कार्यालय में 10 मार्च को 75वीं कराबी निगम स्थापना दिवस एवं विशिष्ट सेवाएँ पखवाड़ा 2026 के समापन समारोह के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया।

75वीं कराबी निगम स्थापना दिवस एवं विशिष्ट सेवाएँ पखवाड़ा के अंतर्गत कार्यालय की ओर से उप क्षेत्रीय कार्यालय, पीन्या के सहयोग से विभिन्न गतिविधियाँ एवं क्रियाकलापो का आयोजन किया गया जैसे जन-स्वास्थ्य जागरुकता संबंधी सेमिनार, स्वच्छता अभियान, बीमित कर्मचारियों, आश्रितों एवं नियोक्ताओं के लिए सुविधा समागम, स्वास्थ्य मेला, वृक्षारोपण इत्यादि। बीमित व्यक्तियों के लिए एमएस रामैया अस्पताल के सहयोग से विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी जाँच कराई गई। नियोक्ताओं के साथ किए गए सुविधा समागम में नियोक्ता की शिकायतों के निवारण के साथ कराबी निगम की विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचित किया गया। समापन समारोह के दौरान उपनिदेशक दरबारा सिंह ने विशिष्ट सेवा पखवाड़ा के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों एवं क्रियाकलापों की रिपोर्ट से सभा को अवगत करवाया।

समापन समारोह के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन क्षेत्रीय निदेशक मनोज कुमार की अध्यक्षता में हुआ। जिसमें मुख्य अतिथि के रुप में डॉ सलमा ज़बीन, राज्य चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहीं, उन्होंने महिला दिवस के अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सशक्त नारी से विकसित समाज का निर्माण हो सकता है।

इस अवसर पर संयुक्त निदेशक मनीष गुप्ता, सुनील कुमार महतो, उपनिदेशक अभिषेक कुमार, महेश कुमार पाण्डेय, संगप्रिय आनंद, सहायक निदेशक श्वेता सिन्हा एवं नागेंद्र कुमार भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। क्षेत्रीय निदेशक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में नारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नारी शक्तिकरण केवल अधिकार नहीं बल्कि समाज के प्रगति की कुंजी है। जब एक नारी सशक्त होती है तो पूरा परिवार और समाज सशक्त होता है। इसलिए नारी को अवसर नहीं, समान अवसर चाहिए- यही असली सशक्तिकरण है। महिला दिवस के अवसर पर सामाजिक सुरक्षा अधिकारी चरिता पी और जागृति त्रिपाठी एवं अन्य अधिकारियों ने महिला सशक्तिकरण एवं समानता संबंधी अपने विचार व्यक्त किए। धन्यवाद ज्ञापन सहायक अश्विन कुमार द्वारा एवं संचालन सामाजिक सुरक्षा अधिकारी राहुल द्वारा किया गया।

प्रतियोगिता

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

बेंगलूरु के लग्गेरे क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा लग्गेरे स्थित मातृश्री मैदान में क्रिकेट स्पर्धा लग्गेरे प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया, जिसमें 12 टीमों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि महेंद्र मुणोत ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए विजेता टीमों को पुरस्कृत किया। आयोजकों ने मुणोत को सम्मानित किया।

मैं यह नहीं बता सकता कि मैं दिल्ली में किससे मिला : डीके शिवकुमार

नई दिल्ली/बेंगलूरु/दक्षिण भारत। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि वह दिल्ली में अपनी बैठक की जानकारी सभी को नहीं बता सकते हैं। कर्नाटक भवन में रिपोर्टर्स से बात करते हुए उन्होंने मज़ाक में कहा, जब मैं दिल्ली आता हूं तो सबसे मिलता हूं। आप रिपोर्ट करते हैं कि दिल्ली के नेताओं ने मुझे इंतज़ार करवाया। तो, मैं इंतज़ार कर रहा होगा। उन्होंने कहा, एक दोस्त के परिवार में शादी थी, इसलिए मैं कल दिल्ली आया था। मैं आज असम प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट से मिला। आज कई प्रोग्राम हैं, जिसमें कई नेताओं को पार्टी में शामिल करना भी शामिल है। वह दिल्ली में नेताओं के साथ अपनी मीटिंग के बारे में एक सवाल का जवाब दे रहे थे।

स्वागत

आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में भारत की जीत के बाद, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मुंबई स्थित अपने आवास पर पहुँचने के बाद मीडिया से बातचीत की।

दीपचंद भंसाली

पदमचंद बोहरा

भंसाली फिर बने जयनगर संघ के अध्यक्ष और बोहरा भी फिर से बने मंत्री

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। स्थानीय श्वेतांबर स्थानकवासी जैन ट्रस्ट जयनगर के ट्रस्टियों की बैठक रविवार को जैन स्थानक भवन में सम्पन्न हुई। मंत्री पदमचंद बोहरा ने आय-व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। ट्रस्ट के मार्गदर्शक सुरेश गुलेच्छा के मार्गदर्शन में आगामी वर्ष 2026-29 के कार्यकाल के लिए नई कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए पुन: दीपचंद भंसाली, मंत्री पद के लिए पदमचंद बोहरा एवं कोषाध्यक्ष पद के लिए गणपतराज लोढ़ा का सर्वसम्मति से चयन किया गया। उपाध्यक्ष पद पर प्रेमप्रकाश मेहता, सहमंत्री महेंद्रकुमार गन्ना एवं संयुक्त कोषाध्यक्ष मानकचंद भंसाली को मनोनीत किया गया।

क्रिया और भावों का हो समन्वय : आचार्यश्री अरिहंतसागरसूरी

जयनगर में चैत्र मास नवपद ओली की आराधना 25 से

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। स्थानीय धर्मनाथ जैन मंदिर जयनगर के प्रांगण में चैत्र मास में आने वाली नवपद ओली की आराधना कराने के लिए राजस्थान श्वेतांबर मूर्तिपूजक संघ की ओर से संघ के पदाधिकारियों ने मंगलवार को आचार्य श्री अरिहंतसागरसूरीश्वरजी से अनुरोध किया। संघ के निवेदन को स्वीकार करते हुए आचार्यश्री ने स्वीकृति प्रदान की। नवपद ओली के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आचार्य श्री ने कहा कि दो ऋतुओं के संधिकाल में यह पर्व आता है। चैत्र मास में आने वाली नवपद ओली की आराधना के वैज्ञानिक पहलू के बारे में उन्होंने कहा कि किसी भी क्रिया का प्राण भाव होता है और भावों को जागृत करने में अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र और काल का सीधा संबंध है जो साधक के भावों को प्रभावित करते हैं। इनमें संधिकाल यानी दो ऋतुओं के बीच का काल है चैत्र मास। ऋतु परिवर्तन में तन, मन को साधना में जोड़ने हेतु आयंबिल तप पर विशेष भार दिया गया है जिसमें सात्विक आहार द्वारा शरीर को पूरा पोषण मिलने पर भी मन में विकार उत्पन्न करने वाले किसी भी प्रकार के तामसी द्रव्यों को स्थान नहीं दिया गया है। संघ के अध्यक्ष चंद्रकुमार संघवी ने बताया कि 25 मार्च से प्रारंभ होने वाली ओली के उपलक्ष्य में आचार्यश्री 24 मार्च को जयनगर संघ में प्रवेश करेंगे। कोषाध्यक्ष भेरूमल भण्डारी ने बताया कि आचार्यश्री का आगामी चातुर्मास जयनगर संघ में निश्चित है।

'धर्म श्रेष्ठ और पवित्र तत्व है और धर्म नमन और आचरण के योग्य है'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, अलसूर के तत्वावधान में महावीर

भवन में आयोजित प्रवचन में साध्वीश्री आदर्शज्योतिजी ने कहा कि धर्म श्रेष्ठ और पवित्र तत्व है। धर्म नमन और आचरण के योग्य है। अहिंसा, संयम और तप रूपी धर्म श्रेष्ठ है और धर्म जीवन में मंगल करता है। अनेक दर्शन धर्म की अलग अलग परिभाषा करते हैं किंतु जो धर्म चित्त में शुद्धता की वृद्धि करे वो ही आत्मा के लिए हितकर होता है। जो हमें कुमार्ग से सन्मार्ग की ओर ले जाए और शाश्वत सुख से परिचय कराए वो ही धर्म हमारा उद्धार कर सकता है।ङ्कङ्क प्रवचन प्रारंभ करते हुए साध्वीश्री आत्मज्योतिजी ने कहा कि श्रावक को सदैव यह मनोरथ रखना चाहिए कि उसकी आरंभ और परिग्रह पर आसक्तिमंद होती जाए और विरक्ति ओर कदम बढ़े ताकि मृत्य के समय समाधि और संथारे का संयोग हो जाए।

धन, परिजन और तन के लिए हम बहुत जी लिए, परन्तु ये हमारे सच्चे साथी नहीं हो सकते हैं। हमारी साधना ही हमारे काम आएगी। उन्होंने आचार्य धर्मदास जी का उदाहरण देते हुए बताया कि जिनशासन की प्रभावना के लिए उन्होंने स्वयं का समर्पण कर दिया और शिष्य के स्थान पर स्वयं संथारा ले कर नौ दिन पश्चात समाधि मरण को प्राप्त किया। अलसूर संघ के मंत्री अभय कुमार बांठिया ने सभा संचालन करते हुए बताया कि साध्वीत्रय का आगामी चातुर्मास चेन्नई में घोषित हुआ है। अध्यक्ष धनपत राज बोहरा ने अतिथियों का स्वागत किया।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

शीतला माता

मंगलवार को शीतला सप्तमी के मौके पर बेलन्दूर क्षेत्र की राजस्थानी महिलाओं ने शीतला माता की पूजा कर बासोड़ा का भोग लगाकर सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की। मंदिर पर अलसुबह से ही महिलाएं सज-धजकर ठंडे पकवान लेकर मंगल गीत गाती हुई घरों से निकली और मंदिर में पूजा की।

सीरवी समाज ने धर्मगुरु दीवान माधवसिंह का किया सम्मान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मैसूरु। जिले के टी-नरसीपुरा तालुक में सोमवार को सीरवी समाज ट्रस्ट द्वारा आई पंथ के धर्मगुरु दीवान माधव सिंह जी का बधावा किया गया। दीवानजी के सम्मान में महिलाओं ने सिर पर मंगलकलश धारण कर शोभा यात्रा निकाली, आईजी गैर मंडल मैसूरु, हेलंदूर गैर मंडल व बन्नूर महिला गैर मंडल द्वारा गैर नृत्य प्रस्तुत किया। यह शोभा यात्रा विभिन्न मार्गो से होते हुए सीरवी समाज के नए मंदिर हेतु क्रय किए गए भूखंड तक निकाली गई। इस मौके पर धर्मगुरु ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी का शिक्षा के साथ संस्कारवान होना अति महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि हर गांव में आईमाता दर्शन हेतु बडेर का निर्माण हो चुका है, ऐसे में सभी बडेरों में प्रत्येक रविवार को सामूहिक रूप से बाल संस्कार पाठशाला लगानी चाहिए ताकि बच्चों में संस्कारों का पल्लवन हो सके। इस अवसर पर समाज की ओर से धर्मगुरु दीवान माधवसिंहजी का सम्मान किया गया। अन्य बडेरों से आए पदाधिकारियों का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर सीरवी समाज टी-नरसीपुरा के अध्यक्ष प्रभुराम सेपटा, उपाध्यक्ष जयराम सोलंकी, सचिव उमाराम बर्फ़ा, सहसचिव सुभाष काग, कोषाध्यक्ष हेमाराम हाँमड़, सहकोषाध्यक्ष टीकमचंद बर्फ़ा, नवयुवक मंडल के अध्यक्ष विनोद काग, सचिव नेमीचंद सोलंकी, माताजी महिला मंडल की अध्यक्ष सुवादेवी पंवार, सचिव लीलादेवी हाँमड़ सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। मंच का संचालन मंगलाराम काग ने किया

आदर्श हाईस्कूल में दसवीं के विद्यार्थियों के लिए 'सायोनारा' कार्यक्रम आयोजित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूर। शहर के आदर्श विद्या संघ द्वारा संचालित मनवरथपेट स्थित केएचएस आदर्श हाईस्कूल में कक्षा दसवीं के विद्यार्थियों के सम्मान में विदाई समारोह 'सायोनारा' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संघ के पदाधिकारी अरविंद जोशी एवं अशोक भंसाली मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस मौके पर अतिथियों ने विद्यार्थियों को आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि विद्यालय में प्राप्त शिक्षा और संस्कार जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी गईं। नृत्य, गीत एवं अन्य कार्यक्रमों ने माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया। विद्यालय परिवार ने भावनात्मक वातावरण में विद्यार्थियों को शुभकामनाओं सहित विदाई दी।ङ्कार्यक्रम का आयोजन प्राचार्य डॉ. प्रज्ञा यादव के मार्गदर्शन में किया गया। उन्होंने विद्यार्थियों को आत्मविश्वास, अनुशासन और निरंतर परिश्रम के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। अन्य शिक्षकों ने भी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने विद्यालय में बिताए अपने अनुभव साझा किए। 10वीं कक्षा की छात्रा नेहा ने स्कूल के अनुभवों को साझा करते हुए शिक्षकों के मार्गदर्शन के प्रति आभार व्यक्त किया। भावुक पलों के बीच विद्यार्थियों ने शिक्षकों और साथियों से विदा ली।

तेरापंथ महिलाओं ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

मंड्या/दक्षिण भारत। शहर के तेरापंथ महिला मंडल द्वारा 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी महिलाओं ने मिलकर नवकार मंत्र से कार्यक्रम की शुरुआत की। मंडल की अध्यक्ष कमलाबाई बुरड़ ने सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। मंत्री सरला बोथरा ने कार्यक्रम की रूपरेखा बताई। ललिताबाई जैन ने एनजीओ मीट की जानकारी दी तथा सभी का स्वागत किया। निर्मला चोपड़ा ने हर एनजीओ के कार्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम को और भी रोचक बनाने के लिए नीतू श्रीश्रीमाल ने सभी महिलाओं के लिए मनोरंजक खेलों का आयोजन किया। डिम्पल भंसाली ने अपना प्रेरणादायक वक्तव्य प्रस्तुत किया। कंचनबाई भंसाली ने सभी का को धन्यवाद दिया।

गढ़ सिवाना गुरु दर्शन यात्रा के दौरान गोलेछा बंधुओं का किया सम्मान

हुब्बल्ली/दक्षिण भारत। वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, गढ़ सिवाना के तत्वावधान में आचार्यश्री विजयराजजी के सान्निध्य में आयोजित होली चातुर्मास भक्ति और आध्यात्मिक वातावरण के बीच संपन्न हुआ। आचार्यश्री विजयराजजी के श्रीमुख से हुए धर्मोपदेश को सुनकर श्रद्धालुओं ने अपने जीवन को धर्म मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। साथ ही आचार्यश्री द्वारा वर्ष 2026 के चातुर्मासों की घोषणा की। इस अवसर पर हुब्बल्ली से स्थानकवासी समाज के अध्यक्ष बाबूलाल पारेख, पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंघी, कार्याध्यक्ष गौतम भुरट, उपाध्यक्ष शांतिलाल खिवेंसरा, महामंत्री प्रकाश कटारिया, कोषाध्यक्ष कांतिलाल बोहरा सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित थे। इस अवसर पर गुरु दर्शन यात्रा के सफल आयोजन में विशेष योगदान देने के लिए हुब्बल्ली संघ के सदस्यों द्वारा गोलेछा परिवार के गौतम गोलेछा एवं जयंतीलाल गोलेछा का सम्मान किया। उपस्थित श्रद्धालुओं ने गोलेछा बंधुओं के समर्पण, सेवा भावना और धर्म के प्रति निष्ठा की सराहना करते हुए उनका सम्मान किया।

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company, 6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51 and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**,
(*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.
HEAD OFFICE : DAKSHIN BHARAT RASHTRAMAT, New Media Company, 6/4, Cantonment Station Road, Bangalore 560051. Editorial : 080-25363030 / 9945488003. For Advertisement : 9945488002 - email : news@dakshinbharat.com/**RNI No. 58061/93.**